News सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-252

पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

'सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता हैं'.

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

इंदौर, मंगलवार 17 दिसम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंतजार खत्म... एक देश, एक चुनाव से जुड़ा बिल आज लोकसभा में होगा पेश

नई दिल्ली। एक देश, एक चुनाव से जुड़ा बहुप्रतीक्षित बिल मंगलवार दोपहर लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल लोकसभा में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश करेंगे। पहले, इस बिल को 16 दिसंबर की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सरकार ने विधेयक की प्रतियां सांसदों को पहले ही वितरित कर दी हैं ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अगर यह विधेयक 17 दिसंबर को पेश नहीं किया जाता है तो सरकार के पास इस सत्र में विधेयक पेश करने के लिए केवल तीन दिन ही शेष रहेंगे। चर्चा है कि सरकार बिल पेश करने के बाद इस पर आम सहमति बनाने के लिए इसे संयुक्त संसीद समिति को भेज सकती है। अब खबरें आई हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को संसद के निचले सदन में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को गत 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी।

भारत विरोधी एजेंडे के बीजेपी के आरोप पर यूएस एंबेंसी ने जताया एतराज

नई दिल्ली। अमेरिका ने बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। यूएस एंबेंसी के प्रवक्ता का कहना है कि यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारुढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के पीछे हमेशा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट (अमेरिकी विदेश विभाग) का हाथ रहा है। गुरुवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद ने यह मसला उठाया था और बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस की मदद से कांग्रेस भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि सोरोस के फंड से चल रहा ओसीसीआरपी भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाता है। इसमें कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल से भी यह आरोप लगाए। इसमें कहा गया कि ओसीसीआरपी का कनेक्शन राहुल गांधी से हैं। साथ ही कहा कि ओसीसीआरपी का कंट्रोल यूएस सरकार के पास हैं

विधानसभा का घेराव नहीं कर सके कांग्रेसी, मंच पर ही दी गिरफ्तारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मप्र सरकार का एक साल पूरा होने पर कांग्रेस नेता सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। इसके लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजधानी के जवाहर चौक में जुटे। कांग्रेस नेताओं ने यहां सभा की। हालांकि यहां से विधानसभा घेराव के लिए नहीं जा सके। सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी। यहीं से उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है। ऐसे में विधानसभा की ओर जाना निषेध है। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मंच पर ही गिरफ्तारी दी। कांग्रेस के विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मोर्चा संभाल लिया था। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई थी। इससे पहले दूसरे जिलों से आ रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भोपाल से लगी सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए थे।

कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक साथ दिखे सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस के विधायक पीसीसी के सामने शिवाजी चौराहे पर इकट्ठा हुए। वे यहां से ट्रैक्टर रैली के जरिये विधानसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शिवाजी नगर चौराहे के पास ही रोक लिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभी नेताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी का सम्मान करुंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है ॉ। मुख्यमंत्री अमेरिका में डायनासोर के अंडे देख रहे हैं। खास बात यह रही कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक साथ मंच पर दिखे।

अपना भी टाइम आएगा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता निराश न हो अपना भी टाइम आएगा। उन्होंने कहा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मध्यप्रदेश की पहचान घोटाला प्रदेश की है। नौजवानों के रोजगार में घोटाला। किसानों के बीज-खाद में घोटाला। जहां देखो घोटाला-घोटाला। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा के मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने बीजेपी, ईडी के दबाव में आत्महत्या कर ली। बीजेपी के लोग उनके बच्चों को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कल अपनी पार्टी के तमाम साथियों से मदद लेकर एक बड़ी गुल्लक उन बच्चों को देने जाऊंगा ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए भविष्य में तकलीफ न हो।

एक साल में कितनी बहनें सुरक्षित हुईं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने संबोधित करते कहा कि सरकार को बने हुए एक साल के ऊपर हो गया है। आधी आबादी यानी महिलाओं से सुरक्षा का वादा था। एक साल में कितनी बहनें सुरक्षित हुईं? रीवा में इनको जिंदा गाड़ने की हिम्मत दबंगों ने दिखाई है। उज्जैन में नाबालिग बेटी को लहूलुहान हमने देखा है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कौनसी बहन को साढ़े 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, जिसकी गारंटी मोदी जी ने दी थी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा इन मुद्दों पर हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे।

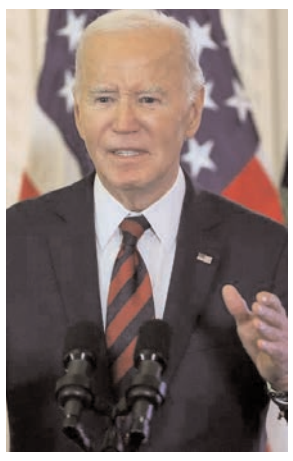

बीजेपी ने लाड़ला नेता योजना की शुरू कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने लाड़ली बहन योजना की राशि 1250 रुपए में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने लाड़ला नेता योजना शुरू की। उस लाड़ला योजना के सबसे पहले लाभार्थी बने रामनिवास रावत। रामनिवास बीजेपी में गए लेकिन विजयपुर की जनता ने, माताओं-बहनों ने गरीब आदिवासी मुकेश मल्होत्रा को विधानसभा पहुंचा दिया। बीजेपी के लाड़ले नेता रामनिवास जी को घर बैठा दिया।

चीन का लहसुन खिला रही भाजपा सरकार कांग्रेस की सभा में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि आज बांग्लादेश के जरिये चीन का लहसुन हमारे यहां आ रहा है। भाजपा सरकार के राज में हमें चीन का लहसुन खिलाया जा रहा है। किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। मैं जब ऊर्जा मंत्री था, कांग्रेस की सरकार 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देती थी। आज 1500 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही है। किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। आज एकजुट होकर इस भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ना है।

जॉर्जिया के रिजॉर्ट में गैस रिसाव से 11 भारतीयों की मौत

त्बिलिसी। जॉर्जिया के एक रिजॉर्ट में 11 भारतीयों की मौत होने का मामला सामने आया है। वहां स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल मरने वालों की पहचान और मौत का कारणों के बारे में नहीं बताया गया है। जॉर्जिया मीडिया के अनुसार ये सभी रिजॉर्ट में काम करते थे और आशंका है कि जहरीली गैस से दम घुटने के बाद सभी की मौत हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को किसी की बॉडी पर निशान नहीं मिला है। पुलिस ने शवों को सुरक्षित रखवा दिया है। जल्द ही उन्हें भारत भेजा जाएगा। जॉर्जिया की पुलिस ने इस मामले में वहां के क्रिमिनल कोड के आर्टिकल-116 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार इस केस में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। रिजॉर्ट प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि बीते 13 दिसंबर को रिजॉर्ट में बिजली नहीं थी। जिसके चलते यहां लगा जनरेटर चलाया गया। बताया जा रहा है कि लगातार जनरेट का धुआं मरने वालों के कमरों में जा रहा था, वह उस समय सो रहे थे। अनुमान है कि जहरील गैस से सभी की मौत हुई है। फिलहाल फोरेंसिक समेत पुलिस की दो टीमें मामले की जांच में लगी हैं। इस बारे में जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछा सवाल

मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से पूछा है कि क्या किसी मस्जिद में जयश्री राम का नारा लगाना अपराध है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि एक मस्जिद में कथित तौर पर नारेबाजी करने वाले आरोपियों की पहचान कैसे की गई ? जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह भी पूछा है कि क्या आरोपियों की पहचान तय करने से पहले सीसीटीवी फुटेज या किसी अन्य तरह के साक्ष्य की जांच की गई थी। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर जय श्रीराम का नारा लगाना धार्मिक भवनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल अपीलकर्ता के वकील से पूछे और निर्देश दिया कि राज्य सरकार को भी शिकायत की एक प्रति दें। इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को उन दो शख्स के खिलाफ कर्नाटक पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जिन पर एक मस्जिद में घुसकर जय श्रीराम का नारा लगाने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अपमानित करने के आरोप थे। इस मामले में दक्षिण कन्नड़ जिले की पुलिस ने दो युवकों को पिछले साल एक स्थानीय मस्जिद में नारेबाजी करने के आरोप में नामजद किया था। इन दोनों पर मस्जिद में घुसकर जय श्रीराम का नारा लगाने और लोगों को धमकी देने के आरोप थे। कथित तौर पर दोनों आरोपियों ने मुस्लिमों को धमकी दी थी कि वे उन लोगों को शांति से रहने नहीं देंगे। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई हरकतें), 447 (अतिचार) और 506 (आपराधिक धमकी) सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

पहले ही दिन से विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार

सिर्फ डेढ़ घंटे चली विधानसभा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

खाद संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने खाद संकट को लेकर सरकार पर चर्चा नहीं कराने के आरोप लगा कर सदन से वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल में नेता प्रतिपपक्ष उमंग सिंघार ने खाद संकट पर चर्चा कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती। इस बीच, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेश के उदय के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए पाक सैनिकों के भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने की बात कही। इस पर विपक्ष ने खाद संकट के मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा कर शोर शराबा शुरू कर दिया, इसके बाद सदन से वॉक आउट कर दिया। विधानसभा के शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हैं। वे बोवनी नहीं कर पा रहे। सरकार खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रही। सरकार बार-बार यूक्रेन की बात करती है। सरकार क्यों नहीं मैक्सिको या मोरक्को से खाद बुलवा पाई। सरकार इस पर बात ही नहीं करना चाहती। अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को चर्चा के लिए विषय लगा होने की बात कहते हुए चर्चा कराने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चर्चा होती रहेगी सरकार तत्काल क्या व्यवस्था कराएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से खाद की कोई व्यवस्था नहीं करने के कारण हम सदन से वॉकआउट करते हैं।

खाद की बोरी लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेता ट्रैक्टर और ट्रॉली पर सवार होकर खाली खाद की बोरी लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने खाद की बोरियों को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश का किसान खाद को लेकर परेशान है। 12 वर्ष पहले जो सोयाबीन के दाम थे, आज भी वही मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा तो ब्लैक में नकली खाद मिल रहा है। जोबट से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने भी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की परेशानी पर गंभीर कदम नहीं उठा रही है। गेहूं का वादा अनुसार समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। लाडली बहनों को तीन हजार रुपए नहीं दिए जा रहे हैं।

प्रश्नकाल में केवल दो ही सवाल हुए पहले दिन सदन में प्रश्नकाल में केवल दो ही सवाल हुए, जहां डबरा से विधायक सुरेश राज्य ने ग्वालियर जिले में मनरेगा में हो रहे कामों में अनियमितता का मुद्दा उठाया, जिस पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जांच कराने की बात कही। इसके अलावा कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गुना जिले के राघोगढ़ के महाविद्यालय में शिक्षकों नियुक्ति से जुड़ा सवाल उठाया था, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया। इन्ही दो सवालों को सदन में उठाया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

तीन में से दो विधायकों ने ली शपथ मध्यप्रदेश में हुए तीन उपचुनावों में तीन नए विधायक चुने गए हैं, जिन्हें शपथ लेनी थी. लेकिन पहले बीजेपी के ही दोनों विधायकों ने शपथ ली है, बुधनी से बीजेपी विधायक रमाकांत भार्गव और अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जबकि विजयपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा सदन नहीं पहुंचे। ऐसे में वे मंगलवार को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेंगे।

इंदौर में निवेश के साथ सामाजिक सुधारों में भी मदद करेंगे एनआरआई

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में सोमवार से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एनआरआई फोरम की वार्षिक मीट का तीसरा संस्करण शुरू हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दुनियाभर से भारत आए एनआरआई का स्वागत किया और कहा कि इंदौर को नई दिशा देने के लिए सभी एनआरआई एकजुट हुए हैं। महापौर ने बताया कि निवेश, समाजसेवा और संबंधों को नई मजबूती देने के लिए सरकार, प्रशासन और एनआरआई कई स्तर पर काम करेंगे। आयोजन में 42 से अधिक देशों के एनआरआई आए हैं। इस साल यह तीसरी वार्षिक मीट है, जो 17 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें व्यापार, संस्कृति और वैश्विक सहयोग के अवसर होंगे। यह दो दिवसीय उत्सव फोरम की सालभर की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेगा, जिसमें निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने से लेकर एनआरआई को इंदौर की परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने वाले आयोजनों का समावेश होगा। इंदौर

से विदेशों में जाकर बसे अप्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दोपहर 3 बजे उद्योगपति विमल तोड़ी ने किया।

इंदौर और वैश्विक समुदाय के बीच मजबूत पुल

महापौर ने कहा इंदौरी एनआरआई फोरम ने इंदौर और उसके वैश्विक समुदाय के बीच एक मजबूत पुल का काम किया है, जो एनआरआई को पूरे वर्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रखता है। यह मंच एनआरआई को उनके शहर के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है, जबकि इंदौर की परंपराओं और यादों को संजोते हुए। पिछले साल हमने मकर संक्रांति के दौरान, फोरम ने पतंगबाजी उत्सव आयोजित किया, जिससे एनआरआई को अपने घर की यादें ताजा हो गईं। रंगपंचमी के दौरान एनआरआई को इंदौर के प्रसिद्ध गेर जुलूस में शामिल होने का अनूठा अवसर मिला, जिसमें उनके आराम और सुरक्षा के लिए विशेष ट्रक का इंतजाम किया गया। फोरम पर्यावरणीय पहलों में भी सक्रिय है। इंदौर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग वृक्षारोपण अभियान में एनआरआई ने बढ़- चढ़कर भाग लिया और इसमें अपनी भागीदारी दी।

इस साल निवेश पर मुख्य ध्यान

इस साल के व्यापार मीट का मुख्य उद्देश्य भारत में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करना है और यह दिखाना है कि एनआरआई देश के विकास में कैसे सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। चर्चा में एनआरआई द्वारा उनके निवास देशों में देखी गई श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि इन प्रथाओं को इंदौर के विकास में कैसे लागू किया जा सकता है। इंदौर के प्रमुख व्यक्तित्व और प्रभावशाली एनआरआई एक पैनल चर्चा में विचार साझा करेंगे, जिससे इंदौर को वैश्विक अवसरों के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।

आज क्रिकेट मैच भी होगा

17 दिसंबर को उत्सव की शुरुआत एनआरआई क्रिकेट मैच से होगी, जो एलबीडब्ल्यू टर्फ पर आयोजित होगा। शाम को कार्यक्रम राजवाड़ा महल में आयोजित संस्कृतिक मिलन के साथ जारी रहेगा, जहां एनआरआई इंदौर की समृद्ध संस्कृति में पूरी तरह से डूब जाएंगे। रात का समापन गोपाल मंदिर में एक विशेष इंदोरी प्रसाद मेनू के साथ होगा, जो एनआरआई को उनके घर के स्वादों से जुड़ने का एक और अवसर प्रदान करेगा।

उद्योगपति विमल तोड़ी बोले- निवेश के लिए इंदौर श्रेष्ठ स्थान

महापौर ने कहा कि तीसरी इंदोरी एनआरआई मीट एक यादगार उत्सव साबित होगी, जो प्रगति, एकता और संस्कृति का प्रतीक बनेगी, और दुनिया भर के इंदोरियों को अपने प्रिय शहर से जोड़ने का कार्य करेगी। उद्योगपति विमल तोड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि इंदौर निवेश के लिए श्रेष्ठ स्थान है। हमने भी बाहर से आकर इंदौर में उद्योग लगाया। इंदौर में निवेश से लाभ के साथ आत्मीयता भी मिलती है।

इंदौर में निवेश के सुझाव मिले

इस दौरान दो पैनल डिस्कशन हुए। पैनल डिस्कशन में सिंगापुर से आईटी युवा उद्यमी साकेत दंडोतिया, अजय कासलीवाल (दुबई), फार्मा इंडस्ट्री से विनी मोटवानी (अमेरिका), रोहन अग्रवाल (जापान), अंशुल लाड (अमेरिका) और मॉडरेट हिमांशु गोयल ने किया। दूसरे पैनल में इंदौर में निवेश के सुझाव मिले और विदेशों की बेस्ट प्रैक्टिस पर डिस्कस की गई। एनआरआई फोरम की संयोजक स्वाति कुणाल टरते ने बताया कि इंदौर के नए उद्यमियों को अपना काम प्रदर्शित करने और निवेश आकर्षित करने के अवसर भी मिले।

ये एनआरआई समिट में हुए शामिल

समिट में अर्पित जैन (नीदरलैंड), सौरव गुप्ता, अंशुल लाड (यूएसए), रॉबिन सुनील पल (आयरलैंड), अंकित अग्रवाल (साइप्रस), शिवम शुक्ला (ऑस्ट्रेलिया), मितेन सोनी, आशीष अग्रवाल (कनाडा), अर्पित बंग, स्नेहा लड्?ढा (न्यूजीलैंड), शीतल जैन, विक्रांत राठौर (सिंगापुर), विकास चौधरी, सोनिया बिल्लौरे (स्वीडन), आनंद शर्मा (जर्मनी), रोहन अग्रवाल, अर्पित चौरडिया (जापान), शांतनु मिश्रा, विपुल डिंडुलकर (यूके) समेत 42 से अधिक देशों के एनआरआई आए हैं।

उज्जैन के सट्टेबाजी कांड में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर ईडी ने की छापेमारी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता विशाल (गोलू) अग्निहोत्री के घर पर छापेमारी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी ने मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस कार्रवाई को उज्जैन के सट्टेबाजी कांड से जोड़कर देखा जा रहा है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सट्टा मामला माना जा रहा है। गोलू अग्निहोत्री, जो इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, को उस समय हिरासत में लिया गया जब वे सोमवार को दुबई से इंदौर लौटे थे। ईडी ने उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार, ईडी ने उनके चंदन नगर स्थित घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान उनके घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, और स्थानीय पुलिस को इस छापेमारी की सूचना नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि जांच में इंदौर और मुंबई के ईडी अधिकारी भी शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई को उज्जैन में मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा से जुड़े सट्टेबाजी मामले की कड़ी में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 14 जून 2024 को उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट सट्टा खेलते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भारी मात्रा में नकदी, चांदी, विदेशी मुद्रा और तकनीकी उपकरण बरामद किए गए थे। पुलिस ने 14.58 करोड़ रुपए नकद, 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड जब्त किए थे। मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा के पास से 500 रुपए के नोटों की 3000 गड्डियां, 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी मुद्रा मिली थी। नकदी की गिनती करने के लिए पुलिस को मशीनें लगानी पड़ी थीं, और यह प्रक्रिया पूरी रात चली थी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं गोलू

विशाल (गोलू) अग्निहोत्री का राजनीतिक कद इंदौर में काफी बड़ा है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का करीबी माना जाता है और वर्तमान में वे इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। 2013 और 2018 में उन्होंने इंदौर-4 विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पाने की कोशिश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उनकी छवि पार्टी में एक प्रभावशाली नेता की रही है। ईडी की इस कार्रवाई ने जहां कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर मुश्किल में डाल दिया है, वहीं भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है। ईडी अब जांच के दायरे को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि बरामद दस्तावेज और सबूतों से नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी की छापेमारी से मध्यप्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि अगर कांग्रेस से जुड़े लोगों के घरों पर कार्रवाई हो रही है तो मामला सीधे-सीधे प्रतिशोध का है और कांग्रेस डरने वाली नहीं है।

बीजेपी ने किया ईडी की कार्रवाई का बचाव

बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई का बचाव किया है। बीजेपी ने मुकेश नायक पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जांच एजेंसियां पार्टी देखकर नहीं बल्कि आपराधिक रिकॉर्ड देखकर कार्रवाई करती हैं। उन्होंने कहा कि गलत करने वाले को जांच एजेंसी नहीं छोड़ेगी। इंदौर में हुई कार्रवाई उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मनोज परमार भी धोखाधड़ी सहित कई मामलों में आरोपी रह चुके थे। इसी तरह इंदौर में भी केंद्रीय जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई कर रही है।

रमेश मेंदोला ने की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर विधानसभा 2 से विधायक रमेश मेंदोला ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। दरअसल, संसद में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। इसके बाद विधायक रमेश मेंदोला ने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का हवाला देकर वीर सावरकर को भारत रत्न से अलंकृत करने की मांग कर दी। मेंदोला ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में मेंदोला ने भारत रत्न देने की मांग करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए सावरकर के अथक संघर्ष और उनके विराट व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए लोकसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दादी इंदिरा फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 1970 में वीर सावरकर पर एक डाक टिकट निकाला था। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1983 में वीर सावरकर की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, ताकि देश के युवा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकें। वहीं वीर सावरकर के स्मारक के लिए आर्थिक सहायता देते हुए लिखे पत्र में इंदिरा फिरोज गांधी ने उन्हें भारत का महान सपूत बताया था। यहीं नहीं लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वीर सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन भी स्वीकृत की गई थी। इन बातों को देखते हुए मेरी मांग है कि सावरकर को भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए।

इधर, कांग्रेस द्वारा उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रति लाए अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल और प्रियंका गांधी से पूछा है कि आखिर दोनों भाई-बहन और उनकी पार्टी जाट समाज से नफरत क्यों करती है? एक्स प्लेटफॉर्म पर किए दो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने राहुल और प्रियंका से पूछा है कि एक सामान्य जाट किसान परिवार से निकले जगदीप धनखड़ का उप राष्ट्रपति पद पर पहुंचना गांधी परिवार को हजम क्यों नहीं हो रहा? क्यों राहुल गांधी बार-बार उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं? मेंदोला ने लिखा कि क्या जॉर्ज सोरेस से मिलकर गांधी परिवार भारत के लोकतंत्र से लड़ाई लड़ेगा?

दो दिन बाद मिलेगी ठंड से राहत, इंदौर में पारा दस से कम पर बरकरार

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है और प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। पिछले सात दिनों से लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जो आने वाले 48 घंटे तक जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 37 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 9 जिलों में पेड़ों की पत्तियों पर बर्फ जमने की संभावना जताई गई है। इंदौर में रविवार को दिन का तापमान 26.7 और रात का तापमान 9.4 डिग्री रहा। इंदौर में पारा पिछले एक सप्ताह से दस डिग्री पर अटका हुआ है। इंदौर और ग्वालियर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। पचमढ़ी और कल्याणपुर इस सीजन के सबसे ठंडे स्थान रहे हैं, जहां पारा 1 डिग्री तक गिर चुका है। भोपाल में बीती रात का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री और जबलपुर में 5 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे यहां शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह शाजापुर, आगर-मालवा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और मंडला जैसे जिलों में शीतलहर और बर्फ जमने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिंगरौली, कटनी, डिंडौरी, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पिछले दो सालों की तुलना में भोपाल और इंदौर की सबसे ठंडी रातें दर्ज की गई हैं, जो इस बार दिसंबर के पहले पखवाड़े में ही देखने को मिली हैं।

22 को एयरपोर्ट पर एटीसी भवन और फायर स्टेशन का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बने नए एटीसी भवन और फायर स्टेशन का औपचारिक शुभारंभ 22 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू होंगे। वे एयरपोर्ट पर सुबह करीब पौन घंटे तक रूकेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया था। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नायडू के इंदौर आगमन की जानकारी मिली है। वे सुबह आएंगे और करीब पौन घंटे एयरपोर्ट पर रहेंगे। इस दौरान एटीसी भवन, नए फायर स्टेशन के साथ एयरपोर्ट के गार्बेज प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए चले जाएंगे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री से एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

विजय दिवस के मौके पर राजवाड़ा पर पुलिस बैंड ने दी शानदार प्रस्तुति

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व और विजय दिवस के मौके पर इंदौर में पुलिस बैंड ने प्रस्तुति दी।

शहर के हृदय स्थल ये राजवाड़ा पर ये प्रस्तुतियां हुई। जिसने भी पुलिस के बैंड को सुना वह मंत्रमुग्ध हो गया। पुलिस के बैंड से एक से बढ़कर एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति दी। सीएम डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को इस पर्व और विजय दिवस के मौके पर पुलिस बैंड ने राजवाड़ा पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व और विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रगीतों और देशभक्ति से ओतप्रोत पुलिस बैंड की प्रस्तुति सभी जिला मुख्यालयों में दी जा रही है। इंदौर में राजबाड़ा पर प्रस्तुति दी गई। राष्ट्रगीतों की धुनों को बजाया गया। इसका उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना से सभी को ओतप्रोत करना है। पुलिस बैंड की प्रस्तुति 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इसमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं गीत और देशभक्ति की धुनों पर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। वे अपने मोबाइल में इस गीतों और धुनों को कैद करते नजर आए।

वन रक्षक परीक्षा में मिले 100 में से 101 नंबर, छात्रों का गंभीर आरोप

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। वन रक्षक और उप निरीक्षक जेल प्रहरी परीक्षा के नतीजे आए हैं। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी विद्यार्थी को 100 में से 101 से ज्यादा अंक मिले हैं, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिन 10 छात्रों ने टॉप किया है, उनमें दो सतना, चार ग्वालियर और चार भोपाल के हैं। इसी तरह का फर्जीवाड़ा पटवारी परीक्षा में भी हुआ था। यह आरोप गोपाल प्रजापति नाम के युवा ने लगाया है। दरअसल, मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वन रक्षक परीक्षा के नतीजे आते ही गड़बड़ियों के आरोप लगने लगे हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इंदौर में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा में तय कुल 100 में से 101 नंबर तक मिलने के आरोप लगाए हैं।

कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

इंदौर में बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि जिन परीक्षार्थियों को पुलिस भर्ती परीक्षा में 60 फीसदी तक अंक नहीं मिले, उन्होंने इस परीक्षा की टॉपर लिस्ट में स्थान पाया है।

राजधानी का नाम नहीं पता और बन गए टॉपर

एक छात्र ने आरोप लगाया कि जिन परीक्षार्थियों को राज्य की राजधानी का नाम नहीं पता वे भी परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वन रक्षक परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी की गई है। एक छात्र को तो 100 में से 101 अंक दिए गए हैं। जबकि, टॉप-10 में शामिल सभी छात्र पूर्व में हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा में 55 से 60 प्रतिशत अंक ही हासिल कर सके थे।

सरकार को दे दी चेतावनी

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच की मांग की। छात्रों का कहना है कि अगर इसी तरह से सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा किया जाएगा तो छात्रों के भविष्य का क्या होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने इस फर्जीवाड़े को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो वे लगातार धरना-प्रदर्शन जारी रखेंगे।

मध्यप्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की भारी कमी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की भारी कमी है। इससे शासन और कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। 1 जनवरी 2024 तक मध्यप्रदेश में 66 आईएएस, 40 आईपीएस और 81 आईएफएस अधिकारियों की कमी है। यह कमी स्वीकृत पदों और कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अंतर से पता चलती है। वहीं, कमी के दो मुख्य कारण हैं। स्वीकृत संख्या से कम अधिकारी कार्यरत हैं और कई अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इससे एक अधिकारी को कई विभागों का प्रभार मिल जाता है। इससे काम पर ध्यान कम हो जाता है और जमीनी स्तर पर अनियमितता की आशंका बढ़ जाती है। दरअसल, मध्य प्रदेश में आईएएस के 459 पद हैं, इनमें 66 खाली हैं। आईपीएस के 319 पद हैं, इनमें 48 खाली हैं। आईएफएस के 296 पद हैं, इनमें 81 खाली हैं।

अधिकारियों की कमी है गंभीर समस्या

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। राज्य में आईएएस अधिकारियों के 459 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 393 अधिकारी ही कार्यरत हैं। आईपीएस के 319 पदों के मुकाबले 271 और आईएफएस के 296 पदों के मुकाबले केवल 215 अधिकारी ही काम कर रहे हैं। इन तीनों सेवाओं में आईएफएस में सबसे ज्यादा कमी है, उसके बाद आईएएस और फिर आईपीएस में। यह कमी राज्य के शासन और प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

केंद्र की तरफ से तय होती है नियुक्ति

की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि, राज्य सरकार अपनी जरूरत के अनुसार पदों की संख्या की मांग कर सकती है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होता है। भोपाल से मिली रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती के पदों पर पदोन्नति के पदों की तुलना में कमी ज्यादा है। आईएएस के 66 खाली पदों में से 56 सीधी भर्ती के और 10 पदोन्नति के हैं। आईपीएस के 43 रिक्त पद सीधी भर्ती के और 5 पदोन्नति के हैं। आईएफएस में 56 पद सीधी भर्ती के और 25 पदोन्नति के खाली हैं।

चयन समिति की बैठकें नहीं हो पा रही

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्यसभा में बताया कि पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने में देरी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रस्ताव न भेजने के कारण है। इसके कारण यूपीएससी द्वारा चयन समिति की बैठकें नहीं हो पा रही हैं या फिर योग्य राज्य सिविल सेवा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति प्रशासनिक क्षमता को और कमजोर करती है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों की कमी के दो कारण हैं। पहला, स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत अधिकारियों की संख्या कम है। दूसरा, कई अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के कम से कम 40 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस वजह से एक अधिकारी को कई विभागों का जिम्मा देना पड़ता है। इससे काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और जमीनी स्तर पर अनदेखी और अनियमितता की संभावना बढ़ जाती है। यह स्थिति राज्य के विकास और सुशासन के लिए चिंताजनक है।

सीधा काम पर असर

इस कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना होगा। नए अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया तेज करनी होगी। साथ ही, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को वापस बुलाने के प्रयास करने होंगे।

पूर्व मंत्री ने विधानसभा में पूछे चुभते सवाल तो बीजेपी खेमे में छाया सन्नाटा!

भूपेंद्र सिंह ने छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार को स्कूलों में बढ़ते अपराधों पर घेरा। सोमवार को शुरू हुए सत्र में उन्होंने इस मामले को प्राथमिकता से उठाने की मांग की। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी शिक्षा विभाग पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्कूलों में छात्राओं के यौन शोषण के मामलों पर सरकार से जवाब मांगा। डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने शिक्षा मंत्री का बचाव किया। भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों में नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण के मामलों पर सवाल उठाए। सागर जिले की खुरई सीट से विधायक सिंह ने कहा कि स्कूल परिसर में छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के जवाब से वे निराश दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रालय नाबालिग स्कूली बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने में विफल रहा है।

कांग्रेस विधायक ने भी घेरा

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी शिक्षा विभाग पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने कहा कि पिछले एक साल में जिन स्कूलों में छात्राओं का यौन शोषण हुआ, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विभाग ने गलत जानकारी दी है। राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से इस मामले पर जवाब मांगा।

डेप्युटी सीएम ने किया बचाव

इस पर डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बचाव किया। शुक्ला ने कहा कि यह कहना कि गलत जानकारी दी गई है, गलत होगा क्योंकि शिक्षा विभाग ने पूछे गए सवालों के आधार पर ही जवाब दिया है। अगर विभाग के जवाब में कुछ कमी है, तो वह अगले दिन आगे जवाब दे सकता है। यह कहना कि गलत जानकारी दी गई है, गलत होगा क्योंकि शिक्षा विभाग ने पूछे गए सवालों के आधार पर ही जवाब दिया है। अगर विभाग के जवाब में कुछ कमी है, तो वह अगले दिन आगे जवाब दे सकता है।

बच्चियों की सुरक्षा है गंभीर मुद्दा

भूपेंद्र सिंह ने चिंता जताई कि स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जयवर्धन सिंह ने भी सरकार से सही जानकारी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देना मामले की गंभीरता को कम करने जैसा है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह एमपी में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वे प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं। प्रदेश की नई सरकार में वे असहज महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी वे अपनी सरकार को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

दो भाइयों सहित तीन को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, तीनों की मौत

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में सिरोंज रोड पर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। तीसरा किशोर है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कार भी पूरी तरह से पलट गई है। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। यह हादसा तब हुआ, जब तीनों एक ही बाइक से शमशाबाद में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बैरसिया पुलिस के अनुसार शुभम कुशवाह पिता प्रेम सिंह (18), मिथलेश कुशवाह (21), नीरज पिता कल्याण सिंह केवट (16) तीनों गुनगा थाना क्षेत्र के ग्राम सागोनी के रहने वाले थे। नीरज और शुभम गांव के स्कूल में एक पढ़ाई कर रहे थे, मिथलेश मजदूरी करता था। नीरज के मौसी के बेटे की शादी रविवार को शमशाबाद में हो रही थी। इसी शादी में शामिल होने के लिए शुभम, मिथिलेश और नीरज रविवार देर शाम एक बाइक से शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। तीनों बाइक से बैरसिया थाना क्षेत्र में सिरोंज रोड पर भूरी पठार से थोड़ा आगे निकले ही थे कि सामने से आ रही कार केयूवी (एमपी-04-सीक्यू-9231) ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार भी पलट गई और बाइक भी खेत में जा गिरी। एक्सीडेंट में बाइक चला रहे शुभम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नीरज ने देर रात और मिथिलेश ने सोमवार सुबह करीब 6 बजे दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों ने पुलिस को बताया कि देर रात स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि उक्त कार चालक किसी अन्य वाहन को टक्कर मारकर भाग रहा था, इन बाइक सवारों को कुचलने से पहले कार चालक एक गाय को भी टक्कर मारी है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे। कार पूरी पलट गई, लेकिन एयरबैग खुलने के कारण चारों को चोट नहीं लगी। हादसे के बाद चारों कार छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसका पता लगा रही है।

भोपाल के हिस्से आया 'चैंपियन ऑफ चैंपियन' और मिस्टर एमपी का खिताब

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल शहर के फिटनेस एथलीट अल्ताफ सुलतान खान ने जबलपुर में आयोजित महापौर ट्रॉफी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियन और मिस्टर एमपी का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। अल्ताफ ने न केवल प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बल्कि ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में भी विजय हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। मध्यप्रदेश के प्रमुख फिटनेस प्लेटफॉर्म्स में से एक महापौर ट्रॉफी में विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अल्ताफ ने अपनी शारीरिक ताकत, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी बेहतरीन परफारमेंस के साथ मिस्टर एमपी का खिताब जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब जीता, जिससे वे मध्यप्रदेश के शीर्ष बॉडीबिल्डर के रूप में उभरकर सामने आए। अपनी इस उपलब्धि पर अल्ताफ ने कहा कि उनकी इस सफलता में उनके कोच इसरार मलिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया। अल्ताफ ने अपनी जीत के बाद कहा कि यह सफलता मेरी मेहनत, समर्पण और मेरे कोच, परिवार और समर्थकों के बिना संभव नहीं होती। मैं अपनी कड़ी मेहनत से भविष्य में भी अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने का प्रयास करूंगा। अल्ताफ सुलतान खान का मानना है कि फिटनेस केवल शारीरिक ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास का भी परिणाम है।

अपनी विरासत रहे आबाद... इकबाल मैदान शहर लगाएगा कलेक्टर से गुहार

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल की पहचान में शामिल इकबाल मैदान पिछले कई सालों से प्रशासनिक पाबंदियों में कैद है। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लगी निषेधाज्ञा को लेकर शहर नाराज भी है और इसको पुनः बहाली के लिए प्रयास भी कर रहा है। इन्हीं फिक्र के साथ सामाजिक संस्था विरासत ए भोपाल ने शहर के बुद्धिजीवियों को जोड़ा। एक विस्तृत चर्चा के साथ एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मुलाकात करेगा। इस दौरान इकबाल मैदान को पुनः गतिविधियों से आबाद करने की मांग की जाएगी। विरासत-ए-भोपाल मंच ने भोपालवासियों की भावना को व्यक्त करते हुए इकबाल मैदान पर लागू धारा 144 को हटाने की मांग की है। मंच इस संदर्भ में एक ज्ञापन कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, जिसमें इस मैदान को पुनः सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए खोलने की अपील की जाएगी। इस मामले को लेकर जुटे शहर वासियों ने यह बात स्पष्ट की कि इकबाल मैदान भोपाल के सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इस मैदान का उपयोग समाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।

रहा है कार्यक्रमों का केंद्र

भोपाल शहर के मध्य स्थित इकबाल मैदान कभी खिरनी वाला मैदान के नाम से मशहूर रहा है। किसी जमाने में यहां मशहूर शायर अल्लामा इकबाल भी अपना समय बिता चुके हैं। भोपाल शीश महल में मेहमान बने इकबाल ने कई यादगार शेरों को आकार भी दिया है। बदलते दौर में इस मैदान के कायाकल्प के साथ यहां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का लंबा सिलसिला भी चला लेकिन पिछले कुछ सालों से इस मैदान को सभी तरह के कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंधित कर रखा है।

हो रहा है बदहाल

कार्यक्रमों से बनी रहने वाली चहल-पहल और यहां होते रहने वाले सुधार और जीर्णोद्धार काम अब रुक गए हैं। नतीजा यहां मंच से लेकर बनी हुई शफीर तक दुर्दशा का शिकार होने लगी है। इस मैदान की खूबसूरती के बाउंड्रीवॉल पर चस्पा किए गए। अलग-अलग शायरों के लिखे हुए शेर पट्टिका भी उखड़ने लगी हैं। यहां बाइक और कार सवारों की धमाचौकड़ी ने यहां के फर्श को भी गड्ढों से भर दिया है।

खत्म हो जाएगी विरासत

विरासत-ए-भोपाल मंच का कहना है कि प्रशासनिक अनदेखी ऐसे ही बरकरार रही तो आने वाले दिनों में शहर की यह खास पहचान अपना वजूद खो देगी।

भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ का लोगो लॉन्च यूपी के मंत्रियों ने दिया मप्र को निमंत्रण

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी भोपाल में प्रयागराज महाकुंभ मेले का लोगो यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने मध्यप्रदेश की जनता को महाकुंभ में आने का आमंत्रण दिया और इस आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बताया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह आयोजन न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बनेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो पिछले कुंभ की तुलना में कहीं अधिक होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुंभ मेले में इस बार कई नई सुविधाएं और तकनीकी नवाचार होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को एक दिव्य और अद्भुत अनुभव मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा और यह इस बार विशेष रूप से ह्लप्लास्टिक मुक्तह्व रहेगा। श्रद्धालुओं को डिजिटल कुंभ का अनुभव मिलेगा और कुंभ स्थल पर स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शुद्ध पेयजल और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, श्रद्धालुओं को उनकी पहचान के लिए रिस्ट बैंड भी दिए जाएंगे। इस मौके पर दोनों मंत्री यूपी सरकार की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सरकारी बंगले भी पहुंचे और उन्हें कुंभ मेला आने का निमंत्रण दिया। नेता प्रतिपक्ष ने उनका स्वागत किया और कुंभ में शामिल होने की सहमति दी। यह आयोजन इस बार पहले से कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित होगा, जिसमें हर पहलू का ध्यान रखा गया है। मंत्रीद्वय ने मध्यप्रदेशवासियों को प्रयागराज में होने वाले इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से व्यापारियों ने की मांग

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने एक बार फिर ट्रेड (कमर्शियल) और प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करने की मांग उठाई है। सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बीसीसीआई पदाधिकारी मिले। अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने कहा, भोपाल को छोड़कर एमपी में यह टैक्स कहीं भी नहीं लिया जा रहा है। इससे व्यापारियों पर बेवजह का दबाव पड़ रहा है। विधायक भगवानदास सबनानी के साथ मंत्री विजयवर्गीय से मिले व्यापारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। इस पर मंत्री ने चर्चा की और आश्वस्त किया कि जब पूरे प्रदेश के किसी भी शहर में कमर्शियल लाइसेंस फीस लागू नहीं है, तो भोपाल एकमात्र ऐसा शहर क्यों है, जहां वाणिज्यिक लाइसेंस शुल्क लागू है। इस विषय पर विसंगतियों को हटाने का प्रयास करेंगे। चेंबर के अजय देवनानी, प्रदीप तिवारी आदि भी मौजूद थे। एक्सपर्ट के अनुसार, नगर निगम सीमा में पहले जो भी व्यापार होता था, उसके बदले कुल 254 कैटेगरी का टैक्स लिया जाता था।

सम्पादकीय

समय की कसौटी पर खरा उतरा है भारत का संविधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में यह उचित ही कहा कि संविधान ने आजादी के बाद भारत के लिए सभी पूर्वानुमानित संभावनाओं को हासिल किया है। एक युवा गणतंत्र के जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने भारत की अच्छी सेवा की है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का निरंतर शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जो जनाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है।

भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में यह उचित ही कहा कि संविधान ने आजादी के बाद भारत के लिए सभी पूर्वानुमानित संभावनाओं को हासिल किया है। एक युवा गणतंत्र के जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने भारत की अच्छी सेवा की है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का निरंतर शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जो जनाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत में हर स्तर पर राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी है। पिछले दशकों में देश में कई तरह के राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने शासन किया है। कुछ विफलताओं को छोड़ दें तो वे ज्यादातर समय देश को आगे ले गए हैं। साल 1975 में आपातकाल लागू करना ऐसा ही एक स्पष्ट उदाहरण है। भारत के संविधान को एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश किया गया था जिसमें एक युवा राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल लचीलापन निहित था। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किए गए। उदाहरण के लिए सबसे हाल का संशोधन संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का था, हालांकि यह प्रावधान अगले परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने कराधान की अपनी साझा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना संभव बनाया और इसके लिए संविधान में प्रासंगिक बदलाव किए गए। इस तरह संविधान ने पिछले वर्षों में भारत को सामाजिक और आर्थिक, दोनों तरह के हितों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। वैसे तो पिछले हफ्ते संसद में आयोजित दो दिवसीय चर्चा में विभिन्न पहलुओं को छुआ गया, लेकिन कई स्तरों पर यह एकतरफा रही। हालांकि, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं था, लेकिन सदस्य इस अवसर का इस्तेमाल इस पर चर्चा के लिए कर सकते थे कि संविधान में अंगीकृत किए गए विचारों पर आगे किस तरह से अमल हो। भारत साल 2047 यानी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें सशक्त बनाना हो। इस संबंध में मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले कुछ प्रावधानों की चर्चा करना मुनासिब होगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या सभी को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है। हालांकि भारतीय राज्य सभी नागरिकों को यह गारंटी उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हुआ है। उदाहरण के लिए हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने तक, कई राज्यों में 'बुलडोजर न्याय' चल रहा था जो कि संविधान के शब्दों और भावनाओं, दोनों के खिलाफ था। देश को संस्थाओं, खास तौर पर न्यायपालिका को मजबूत करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों की वजह से फैसले होने में काफी देरी होती है जिससे आम नागरिकों के हित और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रभावित होती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों में इसे लेकर आमराय है कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो उसे बेहतर गुणवत्ता वाली मानव संपदा की जरूरत होगी। इस संदर्भ में संसद ने अनुच्छेद 21ए (86वां संशोधन) को अपनाकर अच्छा कदम उठाया है जिसके जरिये राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। इसका नतीजा यह है कि पिछले वर्षों में स्कूलों में नामांकन बढ़ गया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही श्रेय की हकदार हैं। हालांकि हाल के कई सर्वेक्षणों, खासकर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में यह साफ हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।

हरित क्रांति की अनचाही विरासत

हरित क्रांति ने देश की किस्मत बदलने में महती भूमिका निभाई, लेकिन अब इसका चक्र उल्टा घूम रहा है। इसके दुष्परिणाम उस समय नीति निर्माताओं ने सोचे भी नहीं होंगे। आज जब किसान आए दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं पर डेरा डाल रहे हैं तो1960 के दशक की हरित क्रांति के परिणाम अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, पानी का संकट, लगातार गिरती मिट्टी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण और तेजी से बढ़ती मुफ्त योजनाओं की संस्कृति जैसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहे हैं।

हरित क्रांति ने देश की किस्मत बदलने में महती भूमिका निभाई, लेकिन अब इसका चक्र उल्टा घूम रहा है। इसके दुष्परिणाम उस समय नीति निर्माताओं ने सोचे भी नहीं होंगे। आज जब किसान आए दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं पर डेरा डाल रहे हैं तो1960 के दशक की हरित क्रांति के परिणाम अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, पानी का संकट, लगातार गिरती मिट्टी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण और तेजी से बढ़ती मुफ्त योजनाओं की संस्कृति जैसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहे हैं।

हरित क्रांति ने भारत को जहां अकाल के जबड़े से बाहर निकाला वहीं, सार्वजनिक कानून अथवा अमेरिका से आयातित पीएल 480 गेहूं पर निर्भरता जैसे अपमान से बचाया और हमेशा तंगदस्ती में जीवन गुजारने वाले हालात से बाहर निकाला। दुर्भाग्य से जिन नीतियों ने हरित क्रांति को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वे ही आज न चाहते हुए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं और केंद्रीय सत्ता उनसे बचाव के उपाय ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। ये संकट सरकार द्वारा किसानों को अधिक से अधिक गेहूं एवं चावल की फसलें उगाने के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली, सब्सिडी पर उर्वरक और एमएसपी की गारंटी अथवा आधिकारिक मंडियों में उपज बेचने का प्रावधान जैसी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो आज असहनीय बोझ बन रहे हैं। एमएसपी को ही ले लें। उपज को बाजार दर पर खरीदने की यह व्यवस्था किसानों को व्यापारियों के उत्पीड़न या शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए लायी गई थी। लेकिन, शक्तिशाली किसान लॉबी के दबाव में लगातार इसे आगे बढ़ाया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अब अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का रूप ले चुकी है। आज सरकार देश में वार्षिक स्तर पर पैदा होने वाले कुल गेहूं और चावल का 30 से 40 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद रही है। देश में 22 अन्य फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती हैं, लेकिन सरकार उन्हें न के बराबर ही खरीदती है। कभी-कभी राज्य सरकारें एमएसपी पर भी प्रीमियम देती हैं। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। इस व्यवस्था से सरकारों की परेशानी और बढ़ जाती है।

फसलों की बिक्री के लिए एमएसपी जैसी नीतियों का बड़े किसानों ने खूब फायदा उठाया और सीमांत या छोटे किसान इससे वंचित ही रहे। देश में ऐसे सीमांत किसानों की संख्या 80 प्रतिशत है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करने के प्रयासों के तहत लाए गए तीन कानूनों से देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने किसानों को अपनी उपज मंडियों के नेटवर्क से बाहर भी बेचने की इजाजत दी थी। फसलों को सीधे निजी व्यापारियों को बेचने की व्यवस्था भी इन कानूनों में की गई थी। अनुबंध पर खेती के रास्ते खोले गए थे और कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था। कृषि उपज की भंडारण सीमा को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था।

उपरोक्त व्यवस्था करने वाले कानून संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना और कृषि लॉबी के सलाह-मशविरे के बिना ही पारित कर दिए गए थे, जिनके विरोध में किसानों, मंडी बिचौलियों और किसान संगठनों ने दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर तंबू गाड़ कर डेरा डाल दिया और एक साल से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को पीछे हटने को मजबूर करने का अंजाम यह हुआ कि कृषि लॉबी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करने लगी। यदि सरकार यह मांग मान लेती है तो इससे सरकार के खजाने पर असहनीय बोझ पड़ेगा।

एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए खड़ा हुआ बवाल हरित क्रांति के अनचाहे नतीजों का केवल एक पहलू है। मुफ्त अथवा भारी सब्सिडी पर पानी, बिजली और उर्वरक जैसी चीजें उपलब्ध कराने से एक और बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इन चीजों पर लगातार प्रोत्साहन पैकेज बढ़ते जाने के कारण हरियाणा और पंजाब में किसान अधिक से अधिक धान उगाने के लालच में पड़ गए। जबकि सब जानते हैं कि बहुत अधिक पानी की खपत वाली यह फसल प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त नहीं है।

दशकों से इस फसल के उत्पादन के कारण यहां पराली जलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। प्रत्येक वर्ष फसल कटाई के बाद जब किसान पराली जलाते हैं तो उसका धुआं दिल्ली-एनसीआर के लिए मुसीबत खड़ी करता है और वायु प्रदूषण के कारण यहां लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है।

गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए वर्ष 2009 से धान की रोपाई को मॉनसून सीजन के साथ शुरू किया गया, ताकि वर्षा जल से सिंचाई और कम से कम भूगर्भीय जल की जरूरत पड़े। लेकिन, इसका परिणाम यह हुआ कि फसल देर से कटने लगी और आगे रबी की फसल बोने को खेत खाली करने के लिए किसानों के पास समय ही नहीं बचता। इसके लिए उन्होंने सस्ता और जल्दी वाला समाधान ढूंढ निकाला और वे धान की पराली को खेतों में ही जलाने लगे, लेकिन इससे वायु प्रदूषण के रूप में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया।

इसी प्रकार उर्वरकों का मामला है, जिसने खेती पर और गंभीर दुष्प्रभाव डाले हैं। वार्षिक स्तर पर कुल उर्वरकों पर दी जाने वाली 1.88 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का दो-तिहाई केवल यूरिया पर खर्च होती है। इसने इस मूल्य नियंत्रित उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे मिट्टी की पोषकता में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। लगभग एक दशक से यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान पोटेशियम और फॉस्फेट के बजाय यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि पंजाब खेती में अपनी आवश्यकता से 61 प्रतिशत अधिक यूरिया उपयोग कर रहा है। इस लेख में कहा गया है, यह बहुत ही हास्यास्पद है कि यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अनाज की उपज बढ़ाने से ज्यादा वातावरण में जहर घोल रही है।

आजादी के फौरन बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों ने किसानों को मुफ्त या उदार सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करानी शुरू की थी। इसका सीधा प्रभाव दिवालिया होतीं राज्य स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) पर देखा जा सकता है और जिन्होंने अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए काफी संघर्ष किया। पैसे की कमी के कारण वे अपने आधारभूत ढांचे को उन्नत नहीं कर सकीं। नतीजतन जब बिजली की मांग चरम पर होती है तो वे हाथ खड़े कर देती हैं।

लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण उद्योग वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार तथा करदाताओं की ओर से वित्तपोषित पांच बेलआउट पैकेज भी नाकाफी साबित हुए और विद्युत व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली। तमाम वित्तीय समर्थन के बावजूद आज खेती हजारों छोटे किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यापारियों पर आवधिक नियंत्रण और किसानों को वित्तीय सहयोग की योजनाओं ने हालात को और खराब बना दिया है। मोदी सरकार ने इसका हल प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी के तौर पर निकाला था, जो सीधे उनके खाते में जाती है। हरित क्रांति से संबंधित मुफ्त योजनाओं की तरह ही इस वित्तीय सहायता वाली सब्सिडी योजना को वापस लेना भी असंभव होगा, जो मुसीबत को और बढ़ाएगा ही।

जर्जर राष्ट्रीय राजमाग- 343 बना हादसों का कारण

बलरामपुर-रामानुजगंज में सफर हुआ मुश्किल

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की बदहाल स्थिति ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि सफर करना जोखिमभरा हो गया है। गड्ढों से भरी इस सड़क पर वाहनों का आना-जाना बेहद मुश्किल हो गया है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमाग-343 का उपयोग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के बाद सड़क पर गड्ढे और बढ़ गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक ग्रामीण ने कहा, हर दिन किसी न किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है। बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार और परिवहन का मुख्य मार्ग है। खराब सड़क के कारण माल ढुलाई में देरी हो रही है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि गड्ढों के कारण गाड़ियां बार-बार खराब हो रही हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। कई बार सड़क की मरम्मत के लिए शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द सड़क मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

राष्ट्रीय राजमाग-343 की दुर्दशा केवल एक सड़क की खराब स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में त्वरित कदम उठाए ताकि लोगों की जिंदगी और व्यवसाय दोनों को सुरक्षित किया जा सके।

(राजीव खरे चीफ ब्यूरो छत्तीसगढ़)

कपिल देव: भारतीय क्रिकेट का वो महानायक जो आज की चमक-दमक में पीछे छूट गया

भारतीय क्रिकेट का इतिहास कई गौरवशाली पलों और प्रेरणादायक कहानियों से भरा है। इनमें से सबसे खास कहानी कपिल देव की है। भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले इस महानायक ने अपनी कप्तानी और प्रदर्शन से देश को 1983 में वह गौरव दिलाया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज, जब भारतीय क्रिकेट के सितारे करोड़ों की कमाई, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पर स्टारडम का आनंद ले रहे हैं, कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी कहीं पीछे छूट गए हैं।

1983 का क्रिकेट विश्व कप भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है। यह बात उस समय की है जब एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की कोई पहचान नहीं थी। इसके पहले के 2 विश्व कप में भारतीय टीम सिर्फ़ एक ही मैच जीत सकी थी। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम को हराकर वह मुकाम हासिल किया, जिसने भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया।

लेकिन यह सफर आसान नहीं था। विश्व कप के दौरान भारत को जिंबाब्वे के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेलना था। भारतीय टीम शुरुआत में ही मुश्किल में थी, क्योंकि मात्र 17 रन पर उसके 5 विकेट गिर गए थे। ऐसे कठिन समय में कपिल देव ने मैदान पर ऐसा करिश्मा किया, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की महानतम पारियों में गिना जाता है।

18 जून 1983 को जिंबाब्वे के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में कपिल देव ने 175 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम को न केवल हार से बचाया, बल्कि एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जो मैच जीतने के लिए काफी था। यह पारी कई मायनों में ऐतिहासिक थी क्योंकि टीम संकट में थी, लेकिन कपिल ने न केवल धैर्य दिखाया, बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के गेंदबाजों को ध्वस्त कर दिया।कपिल की 175 रनों की यह पारी उस समय विश्व कप में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी।इस पारी ने भारतीय टीम को आत्मविश्वास दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में

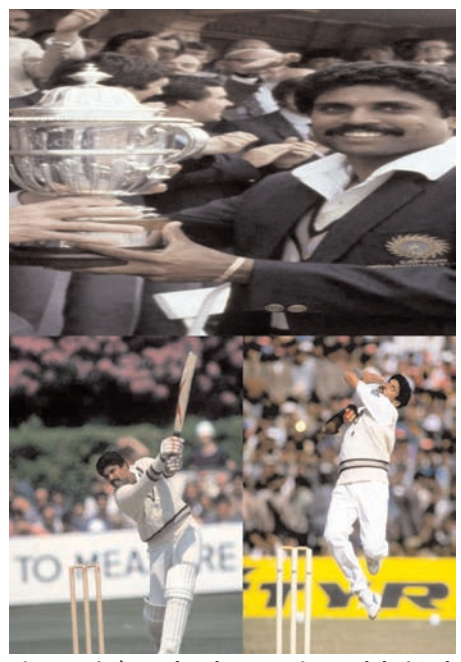

जीत सकती है। दुर्भाग्य से, इस पारी का कोई वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस दिन इंग्लैंड में बीबीसी कर्मचारी हड़ताल पर थे। लेकिन यह पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और आज भी प्रेरणा देती है।

कपिल देव की पहचान उनकी हरफनमौला खेल शैली, अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता से होती है। उन्होंने न केवल बल्ले और गेंद से बल्कि अपने जुझारूपन से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके 434 टेस्ट विकेट और 5000 से अधिक रन उनकी प्रतिभा का प्रमाण हैं। कपिल की कप्तानी में मिली विश्व कप की जीत ने भारतीय क्रिकेट के लिए नया युग शुरू किया। इस जीत ने क्रिकेट को देश में धर्म बना दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

आज का क्रिकेट पूरी तरह बदल चुका है। आईपीएल जैसी लीग, सोशल मीडिया की लोकप्रियता, और ब्रांड एंडोर्समेंट ने खिलाड़ियों को ग्लैमर की दुनिया में पहुंचा दिया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी आज न केवल मैदान पर बल्कि विज्ञापन और मीडिया में भी छाए हुए हैं। इसके विपरीत, कपिल देव का समय खेल के प्रति सादगी और समर्पण का था। उस दौर में खिलाड़ियों की पहचान उनके प्रदर्शन तक सीमित थी, जबकि आज स्टारडम का पैमाना अलग है। कपिल देव ने उस दौर में क्रिकेट खेला, जब सोशल मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं था। आज के खिलाड़ियों की लोकप्रियता में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। कपिल देव ने ग्लैमर से हमेशा दूरी बनाए रखी। वह अपने प्रदर्शन से पहचाने गए, जबकि आज के खिलाड़ी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का हिस्सा बनते हैं। उनके समय में क्रिकेट में वह व्यावसायिक संभावनाएं नहीं थीं, जो आज हैं। कपिल देव जैसे खिलाड़ी केवल देश के लिए खेलते थे, जबकि आज के खिलाड़ी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं।आज की पीढ़ी के लिए 1983 की जीत सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है। उनकी प्रेरणा वर्तमान के सितारे हैं, जिनसे वे डिजिटल माध्यम से जुड़े रहते हैं।

हालांकि कपिल देव आज की चमक-दमक से भले ही दूर हों, लेकिन उनकी महानता और योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। 1983 का विश्व कप और उनकी 175 रनों की पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर है। उन्होंने देश को सिखाया कि खेल में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कपिल देव भारतीय क्रिकेट के पहले महानायक हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित हैं, बल्कि उन्होंने देश को खेल के माध्यम से गर्व का एहसास कराया। भले ही आज के खिलाड़ी ग्लैमर और स्टारडम का आनंद ले रहे हों, लेकिन कपिल देव का योगदान भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। वह उस नींव का हिस्सा हैं, जिस पर आज भारतीय क्रिकेट की यह चमक-दमक टिकी है।

(राजीव खरे चीफ ब्यूरो छत्तीसगढ)

वरदान सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित

रक्तदान शिविर में 30 लोगों ने किया रक्तदान

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर (नागल), पहाड़पुर में वरदान सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बौद्ध ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदाता समाज व मानवता का अनमोल सेवक होता है।आकस्मिक रूप हुई दुर्घटनाओं में घायल व गंभीर रूप से पीड़ितों का जीवन बचाने के लिए दान किया गया रक्त ही काम आता है। अत: हमें रक्तदान को तत्पर रहना चाहिए। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक हर वक्त खुली रहती है। इसमें कोई भी स्वैच्छिक रूप से कभी भी रक्तदान कर सकता

है। इस दौरान जोगेंद्र सैनी, डॉ पुष्पांजलि, सुजीत कुमार, डॉ संजीव सैनी, सतपाल सैनी, अजीत कुमार, नरेंद्र, अक्षय कुमार, रीतु सैनी, आजम शाह आदि मौजूद रहे।

शहीद फौजी राहुल सिंह की प्रतिमा का पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने गांव पहुंचकर किया अनावरण

पूरा देश वीर शहीदों एवं बहादुर वीरों के प्रति नतमस्तक है और उनके परिवारों का भी ऋणी है

जिन्होंने अपने सपूत देश पर न्यौछावर कर दिए : राघव लखनपाल शर्मा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर (रामपुर मनिहारान)। रामपुर मनिहारान विधान सभा क्षेत्र के गांव अंबेहटा चांद निवासी जम्मू में तैनात रहे शहीद फौजी राहुल सिंह की प्रतिमा का गांव पहुंचकर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने अनावरण किया।

ग्रामवासियों द्वारा स्थापित शहीद की प्रतिमा के अनावरण से पूर्व विधिवत हवन-पूजन किया गया। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा द्वारा अनावरण के पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि पंच गँवी की इस पवित्र धरा ने सदा हम सभी को गौरान्वित किया है। पूरा देश वीर शहीदों एवं बहादुर वीरों के प्रति नतमस्तक है और उन परिवारों का भी ऋणी है जिन्होंने अपने सपूत देश पर न्यौछावर कर दिए। शर्मा ने कहा कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने शहीदों का सम्मान करता है और सदैव उनके सिद्धांतों

व कार्यों से सीख लेता है वह सदा समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमें सदा अपने शहीदों को सम्मान के साथ याद रखना चाहिए और नमन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीर शहीदों की वीरता और शहादत का कोई मूल्य नहीं हो सकता किंतु उनको याद कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और वे अपने पीछे जो परिवार छोड़कर चले गए हैं, उनका सम्मान व सहायता करना हर नागरिक का कर्तव्य है। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार शहीदों के परिवारों व स्वतंत्रता सैनानियों को तथा उनके आश्रितों को अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

उपस्थित सैंकड़ों ग्रामवासियों ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीद राहुल सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में राकेश शर्मा यू.एस.ए, शुभम वत्स, वासुदेव भारद्वाज, मांगेराम सिंह, धर्मवीर सिंह, राजवीर फौजी, नीटू प्रधान, श्रीपाल मास्टर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

नि:शुल्क मेडिकल कैम्प लगाकर 140 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई

आरोग्यम एक्यूप्रेशर रिसर्च एंड ट्रेनिंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने लगाया कैम्प

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर । देवबंद, आरोग्यम एक्यूप्रेशर रिसर्च एंड ट्रेनिंग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नि:शुल्क मेडिकल कैम्प लगाकर 140 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें उपचार दिया व स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। रेलवे रोड़ स्थित गुरूद्वारा श्री गुरू नानक सभा में लगाए गए नि:शुल्क मैडिकल कैम्प में आरोग्यम अल्टरनेटिव थैरेपी सेंटर के डा. कुलदीप शर्मा ने सर्वाइकल व शरीर के दर्दो के निवारण के लिए फिजियो थैरिपी , फैजान हॉस्पिटल के डा. मुस्तकीम ने सामान्य रोगों की जांच,कैलाश चंद मेमोरियल हास्पिटल के बीडीएस डा0 पारस जैन ने दांतों की जांच व ओथ्योमेटरिस्ट सौरभ बंसल ने लोगों की आंखों की जांच की। कैम्प के आयोजक डा. कुलदीप

शर्मा ने बताया कि कैम्प में 140 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक इलाज बताया गया साथ ही काफी लोगों के खून की जांच नि:शुल्क की गई। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग के लिए गुरूद्वारा श्री गुरु नानक सभा कमेटी के पदाधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान गुरूद्वारा कमेटी के प्रधान सेठ कुलदीप कुमार, डा. डी.के.जैन, सचिन छाबड़ा, गुरजोत सिंह सेठी, हरविंदर सिंह बेदी, बलदीप सिंह, रमन छाबड़ा, मनदीप शर्मा, प्रशांत त्यागी, हसंदीप कुमार, आशीष कुमार आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चकनाचूर कर रहा है ट्राइबल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ

अनूपपुर, राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया और हाल ही में प्रकाशित विज्ञापन में हुई अनियमितताओं तथा विज्ञापन रद्द कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप पुन: विज्ञापन प्रकाशित करने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ छात्र कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित श्रीवास ने प्रो ब्योमकेश त्रिपाठी, कुलपति (प्रभारी) तथा शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो भुमिनाथ त्रिपाठी को डीन प्रो विकास सिंह की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया है। विश्वविद्यालय में केवल

बिरसा मुंडा के कार्यों पर शोध किया जाना है, लेकिन पीएचडी के विज्ञापन में इन शोधपीठ के लिए किसी भी प्रकार की पीएचडी के प्रवेश देने का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रो श्रीप्रकाशमणि त्रिपाठी और रिटायर्ड प्रोफेसर प्रसन्ना सामल जनजातिया कार्य मंत्रालय के पहले के प्रोजेक्ट तथा बिरसा मुंडा चेयर के करोड़ों रुपए का गबन कर दिए हैं, इसकी बड़ी जांच जरूरी है तथा प्रो सामल को तत्काल शोध पीठ से बर्खास्त किया जाना राष्ट्रहित में आवश्यक है।

इंटर्नशिप के नाम पर एनईपी तथा हजारों छात्रों के साथ धोखा कर बाँटा गया फर्जी डिग्री रोहित श्रीवास ने आगे बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटर्नशिप कराया जाना अनिवार्य प्रावधान है लेकिन पिछले 5 वर्षों में इंटर्नशिप नहीं कराया गया बल्कि सीधे छात्रों को मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इंटर्नशिप और व्यावसायिक कौशल विकास की उपेक्षा करते हुए सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। यह सरासर छात्रों एवं राष्ट्र के साथ धोखा है, इस मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अपील की गई है। पिछले 7-8 वर्षों में विश्वविद्यालय में जनजातीय कल्याण, स्वरोज़गार, और फ्रवोकल फॉर लोकलफ्र जैसे मुद्दों पर ठोस शोध कार्य नहीं हुआ है। जो थोड़े-बहुत शोध राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए थे, उन्हें भी अनावश्यक अड़चनें डालकर रोका गया। हाल ही में प्रकाशित पीएचडी प्रवेश विज्ञापन में सामाजिक न्याय और समावेशन की उपेक्षा करते हुए आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया। यह स्थानीय और जनजातीय युवाओं के साथ बड़ा अन्याय है।

आईजीएनटीयु में नेट/जेआरएफ परीक्षा केंद्र की अनुपलब्धता

रोहित श्रीवास ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय में नेट/जेआरएफ परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण स्थानीय छात्रों को अवसरों से वंचित किया जा रहा है, इसके लिए विवि प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार करके कमाने में व्यस्त रहे। पीएचडी कार्यक्रम में स्लीपर सेल की घुसपैठ और इसे ड्रग तस्करी व अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की शिकायतें हैं। पिछले 5 वर्षों में एनईपी-2020 के उद्देश्यों को लागू करने में विश्वविद्यालय पूरी तरह विफल रहा है।

इनक्यूबेशन सेंटर बन गया है भ्रष्टाचार सेंटर रोहित श्रीवास ने आगे बताया कि पीएचडी का वर्तमान विज्ञापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विरोधी है, एनईपी 2020 में बहुविषयी और लचीली शोध प्रणाली का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान पीएचडी प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों को नज़रअंदाज करती है। स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए बनाए गए लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। बहुविषयी और समग्र शोध का उल्लेख नहीं है।

पीएचडी के विज्ञापन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोर उपेक्षा

रोहित श्रीवास ने आगे बताया कि पीएचडी के विज्ञापन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विदेशी छात्रों की भागीदारी और एमओयु जैसी आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है। शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योगों के बीच संबंध स्थापित करने में विश्वविद्यालय विफल रहा है। विश्वविद्यालयो में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

विज्ञापन को अवैध घोषित कर स्थानीय युवाओं के लिए अवसर देना जरुरी रोहित श्रीनिवास ने आरोप लगाते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर स्थानीय युवाओं और जनजातियों को शोध से वंचित करने के लिए ऐसा फर्जी विज्ञापन निकाला है, ऐसे में पीएचडी प्रवेश के हालिया विज्ञापन को रद्द किया जाना चाहिए तथा स्थानीय छात्रों को एचडी में प्रवेश देने के लिए शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित कराया जाना जरूरी है, पीएचडी कार्यक्रम में बहुविषयी और बहुआयामी शोध को शामिल किया जाए तथा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयु करके गुणवत्तापूर्ण शोध प्रोत्साहित करना जरुरी है।

पीसीएस भर्ती परीक्षा को शान्ति एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराएं सम्पन्न - जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल

अधिकारी अपनी टीम के साथ केन्द्रों का भ्रमण कर सुनिश्चित कराएं आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 22 दिसम्बर 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पीसीएस परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि सभी सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक, केन्द्र पर्यवेक्षक निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षा के सफल संचालन एवं परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लगन, सजगता, आत्मानुशासन एवं समयबद्धता से सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा को पूर्व परीक्षाओं की भांति पूरी पारदर्शिता के साथ नकलविहीन संपन्न करायी जाये। इसकी संवेदनशीलता, शुचिता एवं पारदर्शिता किसी भी स्तर पर भंग न हो, यदि कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी।

मनीष बंसल ने कहा कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। जनपद में काफी संख्या में अभ्यर्थियों का मूवमेंट होगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिये अधिकारी 20 दिसम्बर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के शामिल होने के दृष्टिगत सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ मधुर व्यवहार किया जाए एवं उनके बैग इत्यादि रखवाने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर चिकित्सक की तैनाती करने के साथ ही आपात स्थिति के लिए एक नम्बर जारी किया जाए। उन्होने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि अन्य जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे। पीसीएस परीक्षा जनपद में 26 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। परीक्षा दो

पालियों में पूर्वान्ह 09:30 से 11:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 02:30 से 04:30 बजे तक होगी।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सम्बन्धित सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि अपनी टीम के साथ परीक्षा से 02 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी कमी ना रहे। इसके साथ ही कि परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें।

परीक्षा के लिए निर्धारित 26 केन्द्र- राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज लिंक रोड, सियाराम इण्टर कॉलेज दिनारपुर गागलहेडी, बीडी बाजोरिया इण्टर कॉलेज बेहट रोड, जेवी जैन इण्टर कॉलेज मातागढ कलसिया रोड, एचएवी इण्टर कॉलेज मातागढ ओल्ड कलसिया रोड, इस्लामिया इण्टर कॉलेज ब्लॉक ए ईदगाह रोड, गुरूनानक इण्टर कॉलेज अंबाला रोड, एसएएम इण्टर कॉलेज देहरादून रोड, राजकीय इण्टर कॉलेज नेहरू मार्किट, बीएचएस इण्टर कॉलेज मिशन कम्पाउण्ड, आर्य कन्या इण्टर कॉलेज मटियामहल, जेबीएस हिन्दू कन्या इण्टर कॉलेज रायवाला, गुरूनानक गर्ल्स इण्टर कॉलेज गांधी पार्क, इण्डस्ट्रीयल मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कॉलेज आतिशबाजान कम्बोह का पुल, गौरी शंकर इन्द्रपाल सिंह इण्टर कॉलेज दिल्ली रोड, श्री दिगम्बर जैन कन्या इण्टर कॉलेज छत्ता बासमल, मुन्नालाल एण्ड जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज चिलकाना रोड, जेवी जैन कॉलेज ब्लॉक ए प्रद्युमन नगर, जेवी जैन कॉलेज ब्लॉक बी प्रद्युमन नगर, महाराज सिंह कॉलेज चकरोता रोड, दया चन्द जैन इण्टर कॉलेज अंबाला रोड, इस्लामिया इण्टर कॉलेज ब्लाक बी इदगाह रोड, रमाबाई राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज कोटा, जगदीश प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज कोटा, जनता रोड इण्टर कॉलेज रेलवे रोड नागल एवं किसान विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज बेहट रोड पांसर। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, एंड्राइड फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट परीक्षा केंद्र के अंदर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। परीक्षा केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। कक्ष निरीक्षकों की अच्छी तरह से ब्रीफिंग और ट्रेनिंग करा दी जाये। बैठक में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 प्रवीण कुमार, आयोग से आए समन्वयी पर्यवेक्षक दशरथ मिश्रा, हर्षदेव स्वामी, सैक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कांग्रेस सदन व सडक दोनों स्थान पर करेगी सरकार को वादा खिलाफी याद दिलाने आंदोलन - अनुभा मुंजारे

कांग्रेस के विधानसभा घेराव प्रदर्शन में शामिल हुई बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ

लालबर्रा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर तथा विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में आज भोपाल में विधानसभा का घेराव किया गया.कांग्रेस के विधायकगण डीएपी खाद की बोरी सर और हाथ में लेकर पहुंचे थे.बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई. विधायक अनुभा मुंजारे भी किसानों की खाद की समस्या और सरकार के वादा खिलाफी को लेकर डीएपी खाद की बोरी लेकर शामिल हुई.इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि कांग्रेस सदन व सडक दोनों स्थान पर सरकार को वादा खिलाफी याद दिलाने आंदोलन करेगी. जब सरकार अपने वादा को पूरा नहीं कर रही है तो विपक्ष के रूप में हमें सड़को पर और विधानसभा में भी आवाज उठानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए भी सड़को पर उतरना पड़ा था. जब सरकार ही

कुछ सुन नहीं रही तो हमें सड़को पर उतरना ही पड़ा. कांग्रेस किसान, मजदूर आदिवासी दलित सभी की हितेषी और उनके हितों की रक्षा करने का कार्य कर रही है. विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने चुनाव के पूर्व और बाद में वादा किया है. वादा किया कि हम किसानों की धान 3100 रूपये प्रति किवंटल, गेहूं 2700 और सोयाबीन 6000 रूपये की दर पर खरीदी करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. लाडली बहनो को 3000 रूपये प्रति महीने देने कहा था पर यह राशि नहीं दी जा रही है. खाद का अभाव है और किसानों को खाद नहीं मिल रही. ऐसे में इस सरकार को वादा याद दिलाने का कार्य किया गया है. हमने सडक पर प्रदर्शन किया है और अब सदन के भीतर सरकार से उनके संकल्प और वादा को याद दिलाकर जवाब मांगेंगे.प्रदेश सरकार के एक साल पुरे होने पर मनाये जा रहे जश्न की विधायक अनुभा मुंजारे ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार किस बात का जश्न मना रही और उपलब्धि गिना रही,. सरकार किसानों को धान की दर 3100 रूपये दे नहीं रही है. महिलाओ पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बढे है. आदिवासियों और दलितों का दमन किया जा रहा है, अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.. बता दे कि विधानसभा घेराव में कांग्रेस के सभी विधायकगण मौजूद रहे. घेराव के चलते सुरक्षा के कड़े पहरे थे. बावजूद कांग्रेस ने विधानसभा का पुरजोर घेराव किया और सरकार को उनके वादा याद दिलाने का कार्य किया गया. सरकार की जनविरोधी गतिविधि को सामने लाने का प्रयास किया गया।

अमोली सरपंच के खिलाफ लाम बंद हुए मनरेगा मजदूर.... थाने में की शिकायत

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ। लालबर्रा, सोमवार को ग्राम पंचायत अमोली में परकुलेशन टेंक निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने हेतु पंचायत सचिव,उप सरपंच,मनरेगा सब इंजीनियर अन्य पंचो एवं मजदूर की उपस्थिति में लेआउट डाला जा रहा था जहां पर नशे की हालत में सरपंच किशोर पडवार पहुंचे और अप शब्दों का प्रयोग करते हुए ले आउट की रस्सी खींचते हुए चुने की बोरी को फेंक दिया और कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए काम बंद करवा दिया विदित हो कि उपस्थित मनरेगा मजदूरों में महिला मजदूर भी थी जिनका ख्याल भी सरपंच को नहीं रहा और लगातार वे अपशब्दों का प्रयोग करते रहे जिससे अपमानित उपस्थित पुलिस थाना पहुंचे और एक लिखित शिकायत सरपंच के खिलाफ की है अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।

वहीं शिकायत कर कार्यवाही करने कि मांग करने वालों में प्रमुख रूप से राजेश मेश्राम

पंचायत सचिव,रोजगार सहायक,अफसर कुरैशी उपसरपंच,लकेश पंचेश्वर पंच, तुफान गुप्ता पंच,स्वाती ब्रम्हें पंच, रामेश्वर कावरे पंच,योगेश सोनी पंच, वहीं ग्रामीणों में यशोदा पंचेश्वर,तारा बाई, मनीषा,लक्ष्मी मात्रे,कांती बाई, राजेश्वरी नागेश्वर, कविता, निकिता, यशवंती पंचेश्वर, योगेश विश्वकर्मा,नीलम पंचेश्वर, जितेन्द्र पंचेश्वर सहित अन्य और भी लोगों ने सरपंच पर कार्यवाही कि मांग कि है।

इनका कहना है।

कार्य में बाधा डालने के लिए विधिवत कार्रवाई हो - अफसर कुरैशी

इस मामले में मजदूरों के साथ शिकायत करने थाना पहुंचे उप सरपंच अफसर कुरैशी ने कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए सरपंच पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, हमेशा ही सरपंच द्वारा मस्टर आदि में साइन करने के लिए परेशान किया जाता रहा है इनकी वजह से ही मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

सरपंच ने किया महिलाओं के सामने अपशब्दों का प्रयोग... स्वाति ब्रम्हे

पंच स्वाति ब्रम्हे ने कहा कि सरपंच ने महिलाओं के सामने अपशब्दों का प्रयोग किया है और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है सभी लोग इन्हें लेकर चल रहे थे लेकिन अब पानी सर के ऊपर हो चुका है इसलिए इनकी शिकायत थाने में करने पहुंचे है।

चार दिन पूर्व दी गई थी लेआउट की सूचना-राजेश मेश्राम

पंचायत सचिव राजेश मेश्राम ने बताया कि ले आउट की सूचना सरपंच महोदय को चार दिन पूर्व ही दी गई थी फिर भी वह समय पर उपस्थित नहीं हो पाए और जब लेआउट का काम चल रहा था तब आकर कार्य में बाधा डालते हुए कार्य रुकवा दिया इन पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए जिसके लिए हमारे द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है।

सिंधी संस्कृति और सभ्यता के उत्थान का भव्य आयोजन

भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा के अध्यक्ष विकास सुखेजा के द्वारा सतना का ऐतिहासिक कार्यक्रम

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ। सतना, 15 दिसंबर, रविवार को भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा सतना द्वारा सिंधी संस्कृति, सभ्यता और विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

एग्जिबिशन की शुरुआत कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11:00 बजे से हुआ, जिसमें कपड़ों, आर्ट एंड क्राफ्ट और सिंधी व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। खान-पान के स्टॉलों ने सिंधी संस्कृति के विभिन्न स्वादों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

झूले और मनोरंजन बच्चों के लिए झूलों और विभिन्न गेम्स की व्यवस्था की गई, जो इस आयोजन का आकर्षण का केंद्र बनी।

कार्यक्रम का उद्घाटन शाम 5:00 बजे संत समाज द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में संतों ने सिंधियत और सामाजिक समरसता पर जोर दिया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में सिंधी गीतों के माध्यम से संस्कृति को जीवंत किया गया। इसके अलावा, बच्चों के लिए 1 घंटे की डीजे नाइट भी रखी गई, जिससे युवाओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ।

सम्मान समारोह समाज के पांच वरिष्ठ समाजसेवियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया

श्री लद्दाराम वरंदानी- जिन्होंने समाज में प्रेरणादायक सेवाएं दीं।

श्री ठाकुरदास छाबड़िया- सिंधी सभ्यता के संरक्षण और प्रचार में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित।

श्री दानामल सेनानी जी का भी सम्मान किया गया सिंधी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी उनके

बहुत ही योगदान रहे हैं।

श्री होलाराम वाधवानी- समाजसेवा के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित।

नमन परिवार- यह परिवार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य करता है।

युवा समाजसेवी श्री संजय वाधवानी- समाज के विकास में अपने योगदान से प्रेरणा का स्रोत बने।

विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति-

कार्यक्रम में समाज के विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे-

श्री महेश थारवानी (प्रदेश महामंत्री, भारतीय सिंधु सभा),

श्री लालचंद लालवानी (प्रदेश उपाध्यक्ष),श्री सतीश सुखेजा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला शाखा श्रीमती राखी होतचांदनी(प्रदेश उपाध्यक्ष), श्री विक्रम चौधरी (रीवा संभाग प्रभारी),श्री अशोक चंदवानी , देवेंद्र सत्यवानी प्रदेश मंत्री युवा शाखा भारतीय सिंधु सभा एवं महिला शाखा अध्यक्ष सतना श्रीमती सिमरन होतचंदानी जी

और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी।

वरिष्ठ समाजसेवियों की गरिमामयी उपस्थिति-

इस आयोजन में सतना के वरिष्ठ समाजसेवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे-

श्री श्री चंद मनवाणी, श्री विजय कुमार जगियासी जी, मनोहर लाल अर्तनी ,श्री गोपीचंद कापड़ी जी, डॉ सिरू माल, h s hotchandani जी श्री सतीश सुखेजा,श्री भोजराज माल वाधवानी,श्री मनोहर लाल भोजवानी,श्री बबल अवधवानी,श्री मनोहर लाल वाधवानी,श्री इंद्र लाल कापड़ी,जेठा नंद वाधवानी ,राजेश होतचंदानी ,श्री विनोद गेलानी,अशोक कुमार सुखरामणि,अशोक सचदेव , राजकुमार बजाज, नंद लाल रोहड़ा ,सुरेश बसानी ,किशन खिलवानी ,राजा वाधवानी, दिलीप जिंदवानी ,श्री मनोहर डिगवानी,श्री मनोज बलेचा,विनोद गिलानी ,श्री मनोहर लाल आरतनी,मनोहर सुहानी ,श्री भारत कामदार,श्री मामू वासानी,रवि छूटनी ,सुशील सुखीजा, राजेश कोटवानी ,बिहारी मंगानी,प्रकाश छाबड़िया ,संतोष दौलतानी,

सफल आयोजन की टीम

यह भव्य आयोजन भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा सतना के अध्यक्ष श्री विकास सुखेजा और महामंत्री जैकी छाबड़िया, दिनेश जगवानी, पंकज आहूजा, दिनेश महारचंदानी, गोविंद छाबड़िया, मनोज सुखदानी, सेठी वाधवानी, नितेश गैलानी, विनय सुखेजा, अंकुश नागदेव, गोल्डी खिलवानी, मोनिश मखीजा, सोनू मनवानी, शुभ मातानी, संस्था ने दिया साथ केदार नाथ भक्त मंडल, राम लाला ग्रुप, मीरानी कॉलोनी गणेश उत्सव समिति, सिंध युथ क्लब और झूलेलाल युवा समिति.

इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने दी जूनियर्स को फेशर्स पार्टी

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, श्री रामाकृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस करही सतना की इकाई श्री रामाकृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट के इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा नवप्रवेशित छात्रों के लिए फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। तत्पश्चात छात्रों द्वारा भगवान श्री गणेश की उपासना में नृत्य प्रस्तुत किया और कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा प्रदान की। डांस, सिंगिंग, रैंप वॉक, एक्टमपोर, बैलून गेम्स, म्यूजिक चेयर जैसी विभिन्न गतिविधियां छात्रों द्वारा की गई और कई सारे पुरुस्कार जीते गए। फ्रेशर्स पार्टी में बी. टेक डिपार्टमेंट से शिवेंद्र प्रताप सिंह को मिस्टर फ्रेशर्स और अमन सिंह को मिस्टर पार्टी के अवार्ड से नवाज़ा गया। पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट से हिमांशु प्रजापति को मिस्टर फ्रेशर्स एवं महिमा सिंह को मिस फ्रेशर्स के अवार्ड से नवाज़ा गया। पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट से मिस्टर पार्टी मनीष चर्मकार एवं मिस पार्टी का अवार्ड जाह्नवी मिश्रा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का सफ़ल मंच संचालन बी.टेक डिपार्टमेंट से अथर्व तिवारी एवं शिखा सिंह ने किया। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन शम्मी पुरी, डायरेक्टर शाश्वत पुरी, टेक्निकल विंग डायरेक्टर डॉ. अग्निवेश

अग्निहोत्री, एकेडमिक डायरेक्टर शुभी खरे, फर्स्ट ईयर डीन अभय मिश्रा, हायर सेमेस्टर डीन दीपेश निगम, समस्त विभागाध्यक्ष, स्टाफ मेंबर्स एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

मुरलीधर शर्मा का निधन सतना में सकारात्मक समाजवाद का अंत पंडित कमलाकर चतुर्वेदी

उमेश कुशवाहा । सिटी चीफ सतना, वरिष्ठ भाजपा नेता जिला सहकारी बैंक सतना के पूर्व अद्यक्ष एवम सर्व ब्राह्मण समाज संगठन के सरंक्षक पंडित कमलाकर चतुर्वेदी ने वरिष्ठ समाज सुधारक बार एशोसिएशन के पूर्व अद्यसश एडवोकेट मुरलीधर शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री शर्मा के निधन से सतना जिले में सकारात्मक समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया है । श्री शर्मा का अदालतों में सर्वमान्य अधिवक्ता थे वर्तमान ने उनकी क्षति अपूरणीय है।शोक व्यक्त करने वालो में प्रमुक रूप से सर्व ब्राम्हण समाज के अद्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा प्रमोद तिवारी रवि

शंकर चतुर्वेदी राममणि द्ववेदी महेश तिवारी रामेश्वर तिवारी दिनेश तिवारी ओज कवि सतेन्द्र पांडेय राम निरंजन पांडेय संतोष तिवारी प्यारेलाल शर्मा प्रवेश मिश्रा शनि द्ववेदी देवदत्त हेमन्त अग्निहोत्री मोहित त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

प्रशिक्षण से सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता में सुधार होगा - कलेक्टर

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, सीएम हेल्पलाईन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसी के मद्देनजर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा सीएम हेल्पलाईन को लेकर प्रतिदिन प्रशिक्षण दिलवाए जा रहे हैं, ताकि सीएम हेल्पलाईन की मॉनीटरिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों को किसी प्रकार का कॅन्फ्यूज़न ना रहे। उनके कॉन्सेप्टस क्लियर रहे, उनको कैसे काम करना है, इसलिए प्रतिदिन चार से पांच विभागों को ट्रेनिंग दी जा रही हैं

और यह लगातार चलेगी, जब तक की सारे विभागों की ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। इससे सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

जिला प्रेस क्लब ने किया प्रश्न मंच का आयोजन

जिला प्रेस क्लब द्वारा अनूठे आयोजन की जिलेभर में हो रही प्रशंसा

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, अब तक आमजन की समस्याओं को उठाने वाली और जनहितैषी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने वाली मीडिया का अनूठा आयोजन शाजापुर जिला मुख्यालय पर देखने को मिला। शाजापुर जिला प्रेस क्लब द्वारा रविवार शाम प्रश्न मंच व मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से सवाल पूछे गए और सही जवाब देने वाले को उचित उपहार दिए गए, सही जवाब देकर उपहार पाने वाले के चेहरे खुशी से खिल गए।

यह आयोजन शाजापुर जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष मनीष सिसौदिया द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शाजापुर विधायक अरूण भीमावद थे। अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव रामवीरसिंह सिकरवार ने की। वरिष्ठ पत्रकार मनोज पुरोहित, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रतापसिंह, सर्व हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष आशीष नागर, पत्रकार अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्वागत भाषण अध्यक्ष मनीष सिसौदिया ने दिया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार उमेश टेलर ने किया, आभार पत्रकार कमल सूर्यवंशी ने माना।

सही जवाब पर मिले उपहार

जिला प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रश्नमंच प्रतियोगिता शहर से लेकर प्रदेश तक के सवाल-जवाब से रोचक बना रहा। कार्यक्रम की खास बात रही कि इतनी सर्दी में भी लोग कार्यक्रम में रात 10 बजे तक बने रहे और प्रश्नमंच का आयोजन का लोगों ने भरपूर आनंद लिया, साथ ही सही जवाब देने वालों ने हजारों के उपहार भी जीते।

नगर पालिका उपाध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जीते उपहार प्रश्न मंच का आयोजन कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए था। कार्यक्रम में सवालों का सही जवाब देकर उपहार पाने वालों में नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रतापड्क्षसंह भी शामिल रहे। संतोष जोशी दो सवालों के सही जवाब देकर दो बार विजेता बने।

ये बने विजेता प्रश्न मंच प्रतियोगिता में पूछे गए सवालों के सही जवाब देकर उपहार पाने वाले मुकेश राठौर को प्रेस, पं. संतोष जोशी को मिक्सर और छत पंखा, नरेश्वर प्रतापसिंह को कुलर, नवनीत दूबे को ज्यूसर, अनुराग श्रीवास्तव को हीटर, आदित्य शर्मा को हीटर, बसंत कुशवाह को म्युजिक सिस्टम,

सोनू सोलंकी को म्युजिक सिस्टम, वकार अली को छत पंखा, प्रयांशु शर्मा को प्रेस, भावेश देवतवाल को पंखा, अशफाक खान को हीटर, पवन गोयल को पंखा, अमरसिंह कुशवाह को कूलर, मुकेश दुबे को हीटर, मनोज सक्सेना को हीटर, दिनेश भीकू सोनी को इंडेक्शन, तरूण राठौर को हीटर हित आदि उपहार सही जवाब देने वालें प्रतियोगियों को जिला प्रेस क्लब की और से भेंट किए गए।

स्कूलों में विद्यार्थियों को मोटिवेट कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा - कलेक्टर

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आमजन से कहा है सफाई अभियान में अब यह निश्चय किया है की सभी वार्डों में एक-एक करके सफाई अभियान चलाएंगे। वार्ड नंबर 01 के बाद इस बार रविवार को वार्ड नंबर 02 लिया था और सभी वार्डों में पार्षदगण इस अभियान का नेतृत्व कर रहे है, उनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे है। सफाई कार्य के लिए लगभग 60-70 लोग गत दिवस जुटे और वहाँ पर कुछ समस्याए भी मुझे वार्डवासियों ने बताई, जिसमें एक सबसे बड़ा विषय यह था कि पहाड़ पर जो घर बने हुए हैं, वहाँ से पानी और कचरा नीचे आता हैं, जिसके कारण नीचे की नालियां चोक हो जाती हैं और बारिश में इसमें दिक्कतें आती है। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा संबंधित अधिकारियों से कहा गया है की इसका एक स्थाई समाधान निकालना बहुत जरूरी है, यहाँ पर इसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज़ है, तो ये चीज़ें सामने आई है, निर्देशित किया है की तत्काल कार्रवाई की जाये। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा अब अगला सफाई कार्यक्रम रविवार को वार्ड नंबर 03 में किया जायेगा। अभी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिये स्कूलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में छह माही परीक्षाएं थी, अब कल

से फिर वापस हमारा स्कूलों में दौरा शुरू हो जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और अन्य उपायों पर भी विचार किये जा रहे हैं, जिसमें समाज को साथ में ले-करके स्वच्छता को और बेहतर बना सकें, इसमें एक तरफ जागरूकता के काम, दूसरी तरफ भागीदारी और तीसरी तरफ जुर्माने और दंड की व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने कहा जागरूकता में जैसे की स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, ऐसे अलग-अलग वर्गों के साथ जागरूकता कार्यक्रम किए जायेंगे, दूसरा भागीदारी में अलग-अलग वर्गों को इसमें शामिल करते हुए उनको जिम्मेदारी सौंपना कि आप काम करिए और तीसरा दंडात्मक कार्रवाई में यदि कोई गंदगी फैलाता है, तो गंदगी फैलाने वालों पर दंड की कार्यवाही की जायेगी। इस तरह की रणनीति नगरपालिका द्वारा बनाकर इस पर काम किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल समाप्त, सरकार झुकी

राजीव खरे । सिटी चीफ रायपुर, छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से चल रही राइस मिलर्स की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। राज्य सरकार ने मिलर्स की मुख्य मांगों को मान लिया है, जिससे व्यापार और धान प्रोसेसिंग प्रक्रिया सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने राज्य प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स लंबे समय से धान प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराज थे। उनकी शिकायत थी कि सरकार की तरफ से धान प्रोसेसिंग के लिए भुगतान में देरी होती थी।धान खरीदी और प्रोसेसिंग के नियमों में बार-बार बदलाव किए जा रहे थे।सरकार ने कुछ कर और दंड लगाए थे, जिससे मिलर्स को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा था। हालांकि, मिलर्स ने कई बार अपनी समस्याओं को प्रशासन और सरकार के सामने रखा, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन की इस अनदेखी और संवादहीनता ने मिलर्स को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने शुरुआत में सख्त रुख अपनाया था और संकेत दिया था कि हड़ताल से राज्य की धान खरीदी प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे हड़ताल लंबी खिंचती गई, राज्य की अर्थव्यवस्था और धान खरीदी प्रक्रिया पर इसका गहरा असर दिखने लगा।किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंचने लगे, लेकिन मिलर्स की अनुपस्थिति के कारण उनका धान उठाने में देरी हो रही थी।छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां राइस मिलिंग उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हड़ताल से इस क्षेत्र में ठहराव आ गया।विपक्ष और किसान संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके चलते सरकार को अंततः झुकना पड़ा। हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार ने राइस मिलर्स की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार किया, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि प्रोसेसिंग के लिए मिलर्स को समय पर भुगतान मिलेगा।अतिरिक्त करों और दंडात्मक शर्तों को कम करने का फैसला लिया गया। प्रशासन और राइस मिलर्स के बीच संवाद को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की नौकरशाही और प्रशासनिक सलाहकारों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।मिलर्स का कहना है कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को समय रहते हल करने के बजाय उन्हें टाल दिया। नौकरशाहों ने बार-बार बदलते नियमों से स्थिति को और जटिल बना दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नौकरशाहों और सलाहकारों की अदूरदर्शिता के कारण बैकफुट पर आना पड़ा। इस प्रकरण पर विपक्ष ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपनी अक्षमता और संवादहीनता के कारण यह स्थिति पैदा की। किसानों ने भी नाराजगी जताई कि मिलर्स की हड़ताल के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं, राइस मिलर्स ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल का समाप्त होना राज्य के लिए राहत की खबर है। लेकिन इस प्रकरण ने यह दिखा दिया कि प्रशासनिक अदूरदर्शिता और संवाद की कमी से राज्य को किस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशासनिक प्रणाली में सुधार हो और भविष्य में ऐसी स्थितियां न पैदा हों। राइस मिलिंग उद्योग छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, और इसे मजबूत बनाने के लिए सरकार को दीर्घकालिक नीति पर काम करना होगा।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा कसरावद ने स्थापना दिवस मनाया

खरगोन

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन शाखा कसरावद द्वारा बैंक के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार को अपना 76 वा स्थापना दिवस गणमान्य अतिथियों एवं अमानतदारो का स्वागत फुल माला से किया गया द्य बैंक की उपलब्धियों के बारे मे शाखा प्रबंधक त्रिलोचन सिंग भाटिया एवं सहायक गणक राजेन्द्र यादव के द्वारा दी गई. स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था प्रबन्धक रामकृष्ण पाटीदार द्वारा संस्था के माध्यम से 30 लाख की अमानत

राशि प्राप्त की गई. अमानतदारो को स्वल्पाहार पश्चात अनिरुद्ध शर्मा एवं संदीप पाटीदार द्वारा आभार व्यक्त किया गया.

मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अवसर पर लगा शिविर

प्रशासनिक अमला पहुंचा सुविधाएं देने हितग्राहियों के पास

खरगोन

कसरावद- जन कल्याणकारी शासन और प्रशासन का मुख्य लक्ष्य पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना है। इसी भावना को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व प्रारंभ किया है जो 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निरंतर चलता रहेगा। इस अभियान के तहत कसरावद मे सोमवार को मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का शिवीर वार्ड नंबर 1 से प्रारंभ किया गया। जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए। एवं मंगलवार को वार्ड नंबर 2 में शिवीर लगाया जाएगा उक्त शिविर के प्रारंभ में नगर के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, कर्मचारियों ने शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को मूलभूत के आवेदन प्राप्त कर शिविर में तत्काल निराकरण किया गया है।

मामला रूनखेड़ा रोड पर कुंडेल नदी का

पुलिया डेमेज दुर्घटना की संभावना नहीं जागा प्रशासन

उज्जैन

रुनखेड़ा से धमोत्तर के लिए जाने वाला मार्ग जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बना हुआ है, ओर रुनखेड़ा से लगभग दो किलोमीटर दूरी पर पर कुडेल नदी आती है, ओर इस नदी के ऊपर आवागमन में लिए एक पुलिया बनी हुई है और यह पुलिया वर्तमान में डेमेज (क्षतिग्रस्त) है, मिली जानकारी के अनुसार यह स्थिति पिछली बारिश में ही निर्मित हो गई थी किंतु संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा था और समय रहते अगर कोई ठोस कदम उठाया गया तो ठीक नहीं तो यहां दुर्घटना भी हो सकती है, अगर यहां यात्रियों के आवागमन के दौरान कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा ! जबकि उक्त पुलिया पर यह हालात निर्मित होने की सूचना भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी और मौके पर इसका सुक्षमता से निरीक्षण भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया था किंतु इस ओर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक तो नहीं हुई है !

सरपंच ने दौ बार लिखा पत्र - अरुण खेड़ा से दामोदर के लिए जाने वाले इस रोड पर कूदिल नदी पर बनी पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो रही है इसको लेकर ग्राम पंचायत रन खेड़ा के सरपंच के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को 2 बार आवेदन लिख कर अवगत करवाया !

पीएम आवास में भ्रष्टाचार का आरोप

गींदवानिया में सरपंच सचिव सहायक के खिलाफ ग्रामीण का आक्रोश

उज्जैन

ग्राम पंचायत गिन्दवानिया में नियम विरूद्ध सरपंच, सचिव व सहायक सचिव के द्वारा मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई धांधली की जांच करने एवं कार्यवाही करने हेतु ग्रामीणो ने शासन को शिकायत की है । जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता दुलेसिंह गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत गिन्दवानिया के सरपंच, सचिव व सहायक सचिव द्वारा मनमानी कर शासन निधि से किये जाने निर्माण कार्यो में धांधली कर गबन किया गया है । गांव में जो स्टापडेम एचडीएफसी बैंक व आशा खाचरौद के द्वारा बनाया गया था जो कि इन लोगो ने मनरेगा में मिलकर उसके 2.50 लाख रूपये निकाल लिये है। साथ ही श्मशान घाट पर पौधारोपण के लिये 75 हजार की राशि भी निकालकर गबन कर ली गई है जबकि एक भी पौधा नहीं लगाया गया है । इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वास्तव में हितग्राही है उन्हे अपात्र बताकर सूची से नाम हटा दिये गये है तथा फर्जी नाम जोडकर योजना का लाभ दिया गया है। उक्त धांधली की शिकायत जनसुनवाई के साथ-साथ सीएम हेल्पलाईन में भी की गई है पर कार्यवाही नहीं की गई। गांव में कई हितग्रही ऐसे है जिन्हें वास्तव में घर की आवश्यकता है परन्तु उन्हे शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि जिन लोगो के पहले से पक्के मकान है एवं जमीने है उन्हें योजना के अंतर्गत राशि दिलाई गई है। सरपंच, सचिव व सहायक सचिव के द्वारा इसी प्रकार आगे भी धांधली कर गबन किया जाता रहेगा तो गांव का विकास नहीं हो पायेगा। ग्रामीणो ने शासन से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनः सर्वे करवाकर वास्तविक पात्र हितग्राही को लाभ दिलवाये एवं सरपंच, सचिव व सहायक सचिव के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाए ।

ग्राम पंचायत भगोर में आयोजित हुआ जनकल्याण पर्व

विभिन्न योजनाओं में आए 89 आवेदन

झाबुआ

मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान योजनाओं के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतो में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है । जिसमें कुल 34 हितग्राही मूलक एवं 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के तहत हितग्राही लाभान्वयन योजनाएं चलाई जा रही है ।इसी कड़ी में आज ग्राम भगोर में जन कल्याण पर्व का आयोजन ग्राम पंचायत भवन पर रखा गया । जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया । जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग , खाद्यान्न विभाग आदि ने अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत सी ई ओ पी .सी .वर्मा , पंचायत इंस्पेक्टर लालू सिंह अजनार, ग्राम सरपंच भूरी बेन भाबोर एवं विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सी ई ओ श्री वर्मा ने कहा कि इस शिविर का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो । और जो छूट गए हो उन्हें भी इसका लाभ मिले । और प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी शीघ्र हो ,पात्र व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए ।शिविर में आवेदन की संख्या ज्यादा होना चाहिए ।वही पी एच ई एवं एम पी ई बी विभाग से अनुपस्थित जिम्मेदार कर्मचारियों को लताड़ भी लगाई । उपस्थित ग्रामीणों को पीसीओ अजनार ने भी संबोधित किया और अन्य योजनाओ की जानकारी देते लाभ लेने हेतु आवेदन देने को कहा। इस तरह आज के इस जनकल्याण पर्व में स्वास्थ्य विभाग में 8, ग्रामीण विभाग विकास विभाग में 5, सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्त में पेंशन हेतु 2, खाद्यान्न विभाग में उज्ज्वला एवं खाद्यान्न हेतु 24 , एसबीएम के 4 , पशुपालन विभाग में 12 , राजस्व में 5 , पी एच ई विभाग में 2, एवं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास विभाग में 27 आवेदन प्राप्त हुए। इस जनकल्याण पर्व में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद झाबुआ की संस्था संस्कृति युवा मंडल समिति द्वारा भी सहयोग किया गया और हितग्राहीयों द्वारा आवेदन दिलवाए गए। इस कार्यक्रम में सचिव भूरजी कटारा, मोबिलाइजर मुन्ना मेड़ा , रोजगार सहायक विकास वर्मा , एवं कश्मीर भाबर , राजेश बैरागी , अर्चना बैरागी एवं अमृत नायक आदि का सहयोग रहा ।

मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व के तहत पुलिस बैण्ड ने दी प्रस्तुति

हरदा मुख्यमंत्री जनकल्याण पर्व के तहत जिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को स्थानीय प्रताप टाकीज चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में जिला पुलिस बल के बैण्ड ने अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में पुलिस बैण्ड द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीतों पर संगीतमय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेड़िया, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सविता झानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती राजेश्वरी महोबिया सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सभी अधिकारी जनकल्याण के शिविरों में उपस्थित रहें - कलेक्टर सुश्री बाफना

विभागीय समन्वय एवं समयसीमा पत्रों की समीक्षा संपन्न

शाजापुर

जनकल्याण अभियान 11 दिसम्बर से 26 जनवरी 2025 एवं जनकल्याण पर्व 11 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2024 के व्यापक क्रियान्वयन के लिए शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, सभी अधिकारी शिविर में जायें एवं चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने आज विभागीय समन्वय एवं समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये। कलेक्टर सुश्री बाफना ने बैठक में निर्देश दिये कि सभी जिला अधिकारीगण जनकल्याण अभियान एवं जनकल्याण पर्व के लिए आयोजित किये जा रहे शिविरों में उपस्थित रहें और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजनों को अवगत कराएं। साथ ही पात्र हितग्राहियों का चयन कर शासन की योजनाओं से लाभांवित भी करें। उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहें। इस दौरान कलेक्टर सुश्री बाफना ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए चयनित शिकायतों के समाधान की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय शाजापुर एवं सिविल अस्पताल शुजालपुर द्वारा मरीजों के उपचार एवं रेफर प्रकरणों की समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बायोमेट्रिक से नहीं बन रहा है, ऐसे बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड फेस रीडिंग से बनवाने तथा आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने विगत दिनों जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए लगाए गए अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि जिला चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान बताए गए कार्यों को समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण के संबंध में निर्देश दिये कि जिन हितग्राहियों को प्रथम किश्त प्रदान कर दी गई है उनके द्वारा 45 दिनों के भीतर यदि उपयोगिता के साथ द्वितीय किश्त की मांग नहीं की गई है तो ऐसे हितग्राहियों का वेरीफिकेशन करें। इस अवसर पर संबल सत्यापन, खेत तालाब, निजी खेतों में फालोद्यान, तालाब निर्माण की समीक्षा कर खेत तालाब बनाने वाले हितग्राहियों का वेरीफिकेशन कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने बैठक में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर, जल कर एवं स्वच्छता कर की वसूली की भी समीक्षा की। साथ ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के वसूली के लंबित प्रकरणों में वसूली बढ़ाने के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर, अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर श्रीमती अर्चना कुमारी, शाजापुर सुश्री मनीषा वास्कले व गुलाना श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री राजकुमार हलदर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

जॉर्जिया में जहरीली गैस से 11 भारतीयों की दर्दनाक मौत

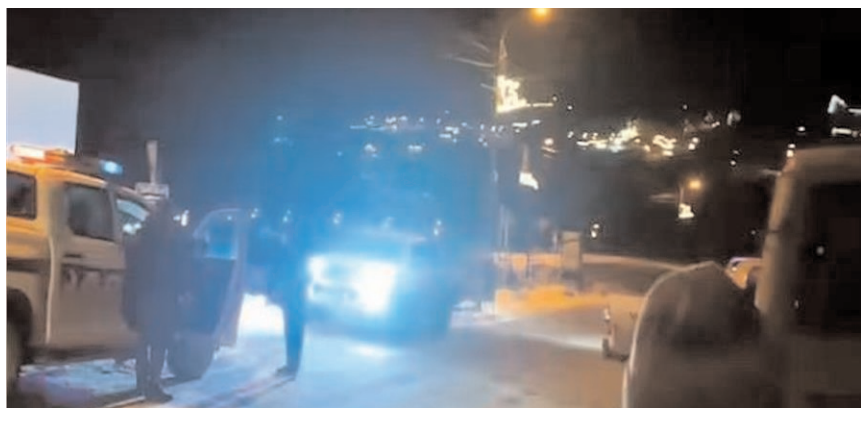

इंटरनेशनल डेस्क: जॉर्जिया के पर्वतीय रिसॉर्ट गुदौरी के एक रेस्तरां में 11 भारतीय नागरिक मृत पाए गए। यहां स्थित भारतीय मिशन ने सोमवार को यह जानकारी दी। जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती जांच में किसी भी तरह की चोट या हिंसा के कोई संकेत नहीं मिले।

स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि सभी की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है। भारतीय मिशन ने यहां जारी एक बयान में शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मिशन ने कहा कि वह मारे गए भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और मामले में हरसंभव सहायता दी जाएगी।

इससे पहले दिन में, त्बिलिसी में स्थित भारतीय मिशन ने कहा था कि सभी 12 मृतक भारतीय नागरिक थे। बयान के मुताबिक, सभी मृतक उक्त भारतीय रेस्तरां में बतौर कर्मचारी काम कर रहे थे और उनके शव दूसरी मंजिल पर स्थित शयन कक्षों में पाए गए। सूत्रों ने बताया कि जान गंवाने वाले व्यक्ति उत्तर भारत से ताल्लुक रखते थे। जॉर्जिया के आंतरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मृतकों में 11 विदेशी हैं जबकि एक जॉर्जियाई नागरिक है।

स्थानीय पुलिस ने जॉर्जिया की अपराध संहिता की धारा 116 के तहत जांच शुरू की है। यह धारा लापरवाही से जुड़ी मौत का मामला है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक, शयन कक्षों के पास एक बंद स्थान में विद्युत जनरेटर रखा गया था, जिसे संभवत: शुक्रवार रात विद्युत आपूर्ति बंद होने के बाद चालू किया गया था। इसने बताया कि 'मौत का सटीक कारण जानने के लिए फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है।

शिक्षक और छात्र की हत्या बाद की खुदकुशी

अमेरिका में क्रिसमिस से पहले ईसाई स्कूल में 15 वर्षीय छात्रा ने की गोलीबारी

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी प्रांत विस्कॉन्सिन के स्कूल में सोमवार को 15 वर्षीय छात्रा द्वारा की गई गोलीबारी में एक शिक्षक और अन्य छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 'एबंडैंट लाइफ स्कूल में गोलीबारी करने वाली छात्रा की भी मौत हो गई है। पुलिस ने सोमवार रात संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गोलीबारी की यह घटना स्कूल के एक अध्ययन कक्ष में हुई और इसकी सूचना दूसरी कक्षा के एक विद्यार्थी ने पुलिस को दी। विस्कॉन्सिन पुलिस ने बताया कि छात्रा की पहचान नताली रूपनो के रूप में हुई है। मैडिसन पुलिस प्रमुख शॉन बार्न्स ने बताया कि गोलीबारी में छह अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों में दो छात्र भी शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

स्कूल में गोलीबारी की घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की। बाइडेन ने कहा कि स्कूल में बचों को पढ़ना-लिखना सीखना चाहिए न कि बंदूक चलाना और हिंसा करना। बाइडन ने देश में बढ़ रही बंदूक संस्कृति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि देश की संसद को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

बार्न्स ने बताया कि एक शिक्षक और तीन छात्रों को मामूली चोट आई हैं, जिनमें से दो को सोमवार शाम ही छुट्टी दे दी गई। बार्न्स ने कहा, ''इस इमारत में हर बचा, हर व्यक्ति पीड़ित है और शायद इस जख्म से कभी नहीं उबर पाएगा... हमें यह पता लगाने और समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर हुआ क्या। 'एबंडैंट लाइफ स्कूल में प्राथमिक शाखा की निदेशक बारबरा वियर्स ने कहा कि गोलीबारी की घटना के दौरान छात्रों ने ''घबराए बिना खुद को अछे से संभाला। पुलिस ने कहा कि जब अधिकारी घटनास्थल पहुंचे तो वहां उन्होंने हमलावर छात्रा को मृत पाया। उसने बताया संभवत: हमलावर ने खुदकुशी कर ली थी। बार्न्स ने उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। बार्न्स ने कहा कि किस मकसद से गोलीबारी की गई इस बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस हमलावर छात्रा के माता-पिता से इस बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि गोलीबारी पहले से सुनियोजित थी या नहीं। 'एबंडैंट लाइफ एक गैर-सांप्रदायिक ईसाई स्कूल है जिसमें किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक लगभग 400 छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को मैडिसन के एक घर में तलाशी वारंट जारी किया गया था। स्कूल के किसी व्यक्ति ने पूर्वाह्न 11 बजे से कुछ समय पहले पुलिस को फोन कर हमलावर की सूचना दी थी। बार्न्स ने कहा कि पुलिसकर्मी केवल पांच किलोमीटर दूरी पर थे, जहां वे प्रशिक्षण ले रहे थे। वे शुरुआती फोन के तीन मिनट बाद स्कूल पहुंचे और तुरंत इमारत में चले गए। बार्न्स ने कहा कि जब गोलीबारी हुई, तब कक्षाएं चल रही थीं। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि स्कूल में यह घटना वास्तव में कहां हुई।

घटना के बाद पुलिस ने स्कूल के आस पास की सड़कें बंद कर दीं और जांच कर रहे अधिकारियों की मदद के लिए मौके पर संघीय एजेंट उपस्थित थे। घटना में पुलिस ने कोई गोलीबारी नहीं की। एक बयान में राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस घटना का हवाला देते हुए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से बंदूक के संबंध में सार्वभौमिक पृष्ठभूमि की जांच, 'नेशनल रेड फ्लैग लॉ और कुछ बंदूक प्रतिबंधों को पारित करने का आह्वान किया। बाइडन ने कहा, ''कभी भी इस तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो बचों, उनके परिवारों को आघात पहुंचाए और पूरे समुदाय को अलग-थलग कर दे। उन्होंने विस्कॉन्सिन के गवर्नर टोनी एवर्स और मैडिसन के मेयर सत्या रोड्स-कॉनवे से बात की और अपना समर्थन दिया। एवर्स ने कहा कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई बचा या शिक्षक स्कूल जाए और कभी घर वापस नहीं आए।

यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी का दावा

कुर्स्क में युद्ध में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिक

इंटरनेशनल डेस्क। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के साथ युद्ध में उत्तर कोरिया के लगभग 30 सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक एजेंसी ने अपनी टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि ये सैनिक कुर्स्क के तीन गांवों के पास मारे गए।

कुर्स्क वह सीमावर्ती क्षेत्र है,जहां रूस पिछले चार महीनों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है जो यहां कब्जा किए हुए है। एजेंसी के अनुसार कुर्स्क के एक अन्य गांव के पास कम से कम तीन उत्तर कोरियाई सैनिक लापता हो गए हैं।

उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत

यूक्रेनी अधिकारियों के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। यह पहली बार है जब युद्ध के दौरान उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर आई है। रूस के क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने इन दावों पर टिप्पणी के लिए सवाल रूस के रक्षा मंत्रालय को भेजे हैं लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

रूस को उत्तर कोरिया से समर्थन

अमेरिका के रक्षा विभाग और यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया ने रूस को युद्ध में मदद के लिए लगभग 10,000 सैनिक भेजे हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत रूस के युद्ध प्रयासों के लिए अपनी पूरी सहायता देने का वचन दिया था। यूक्रेनी अधिकारियों ने 5 नवंबर को बताया था कि उनकी सेनाओं ने पहली बार रूस के समर्थन में भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों से जंग लड़ी थी।

पेंटागन ने की पुष्टि

पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने भी पुष्टि की कि कुर्स्क में कुछ उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं लेकिन मारे गए या घायल सैनिकों की संख्या स्पष्ट नहीं है।

राइडर के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को मुख्य रूप से पैदल सेना के रूप में इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने लगभग एक हफ्ते पहले ही युद्ध अभियानों में भाग लेना शुरू किया था।

भाषाई बाधाएं और युद्ध की कोऑर्डिनेशन

सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों के बीच भाषा की बाधा के कारण युद्ध की रणनीति और समन्वय में कठिनाई हो सकती है। इसके बावजूद रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग जारी है खासकर रूस की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि यूरोप और एशिया में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती से नए खतरे पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण रूस को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम संतुलित और सटीक होंगे ताकि हथियारों की होड़ से बचा जा सके।

यूक्रेन में बढ़ती स्थिति

पिछले साल के मुकाबले रूस को कुर्स्क के अलावा अन्य मोर्चों पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में लगातार बढ़त बनाई है।

रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने सोमवार को दावा किया कि रूस की सेना यूक्रेन में लगातार बढ़त हासिल कर रही है और हाल ही में इस प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना अब एक दिन में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रही है।

इस प्रकार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में उत्तर कोरिया की बढ़ती भूमिका और संघर्ष की जटिलताएँ बढ़ती जा रही हैं जबकि रूस की सेना विभिन्न मोर्चों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है।

दर्दनाक हादसे से परिवार में मचा कोहराम

गीजर की गैस लीक होने से दो बहनों की मौत

नेशनल डेस्क. भोगपुर के गांव लड़ोई में गीजर की गैस लीक होने से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 12 साल की प्रभजोत कौर और 10 साल की शरनजोत कौर की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ, जब दोनों बहनें बाथरूम में कपड़े धोने के लिए गई थीं। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

घटना की जानकारी

मृतक बहनें प्रभजोत कौर (12) और शरनजोत कौर (10) के माता-पिता अलग-अलग देशों में रहते हैं। मां तानिया दुबई और पिता संदीप कुमार पुर्तगाल में काम करते हैं। दोनों बच्चियों की देखभाल दादा-दादी करते थे। इस दुखद घटना के बाद तानिया जब दुबई से भारत लौटीं, तो सोमवार दोपहर को दोनों बच्चियों का संस्कार किया गया। थाना भोगपुर के एसएचओ यादविंदर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि दोनों बच्चियां अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद बाथरूम में गई थीं, जहां गीजर की गैस लीक हो गई और यह हादसा हुआ। संदीप कुमार और तानिया के तीन बच्चे प्रभजोत, शरनजोत और 8 साल का बेटा हरजोत सिंह थे। हरजोत सिंह ने पुलिस को बताया कि रविवार को दादी किसी काम से घर से बाहर गई थीं, जबकि वे दोनों बहनें खेल रही थीं। जब दादी और दादा लौटे तो उन्हें घर में दोनों बहनें मृत पड़ी हुई मिलीं। दादा-दादी का कहना था कि वे बच्चों को हंसते-खेलते छोड़कर गए थे, लेकिन जब लौटे तो उनके सामने यह दिल दहला देने वाली स्थिति थी।

गीजर से गैस लीक के कारण मौत इस हादसे की वजह गीजर से लीक होने वाली गैस को बताया जा रहा है। गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। अगर गीजर को सिलेंडर से जोड़ा जाता है, तो उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती हैं। जलने पर ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड (ष्टह्व2) का रूप ले लेती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है, तो व्यक्ति सबसे पहले बेहोश हो जाता है। अगर गैस का लीक जारी रहता है तो यह मौत का कारण बन सकती है, जैसा कि इस हादसे में हुआ।

हादसे के बाद की स्थिति

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। परिवार के सदस्य खुद को दोषी मान रहे हैं और मां तानिया तो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इस हादसे ने गीजर से गैस लीक होने के खतरों को एक बार फिर उजागर किया है।

सावधानी बरतने की जरूरत

इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि गीजर का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा बहुत जरूरी है। यदि गीजर का सही तरीके से मेंटेनेंस न किया जाए, तो यह गैस लीक करने का कारण बन सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। घरों में गीजर का इस्तेमाल करते वक्त विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और गैस लीक होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना चाहिए।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार मानवता के मूल्यों पर गहरा आघात

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा ने मानवता के मूल्यों पर गहरा आघात किया है। मुख्यमंत्री ने विजय दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए 1971 के युद्ध में भारत के लगभग 3900 जवान शहीद हुए। वहीं, बांग्लादेश अब सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर हमारे देश के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चुप्पी साधने वाले लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि छोटी-छोटी घटना पर कैंडल मार्च के साथ ही संसद बाधित करने वाले अब पूरी तरह गायब हैं। उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, जिन्हें वोट के लिए बांग्लादेश का नरसंहार तक नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपनी चिंताओं से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अवगत करा दिया है। धामी ने कहा भारत हमेशा से शांति और सहिष्णुता का पक्षधर रहा है। लेकिन, हमारी सद्भावना को हमारी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। हम अगर 'धूल से फूल बनाना जानते हैं तो हम 'धूल में मिलाना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। सीएम ने कहा 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने विश्व को दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। बल्कि, जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जो दुनिया के सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय घटना के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले 3900 भारतीय सैनिकों में उत्तराखंड के 255 बहादुर सपूत शामिल थे। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने के साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रितों को राय सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया गया है।

शहीदों की वीरांगनाओं और माताओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी

वहीं, आगे धामी ने कहा कि वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की है। जबकि अनुदान राशि को लेकर परिवार में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए राय सरकार ने शहीदों के माता-पिता और पत्नी दोनों को अनुदान राशि में समान अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राय के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को भी राय परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569